

an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Constitution (One Hundred and Nineteenth Amendment) Bill, 2013, as passed by Rajya Sabha (Discussion Concluded and Bill Passed).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 23A – The Constitution (One Hundred and Nineteenth Amendment) Bill, 2013 – of the Supplementary List of Business.

Hon. Minister.

विदेश मंत्री तथा पृथ्वी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुष्मा स्वराज) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ:-

"कि भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों का अर्जन और कतिपय राज्य क्षेत्रों का बांग्लादेश को अंतरण किए जाने को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक को विचार के लिए रखते समय मुझे सदन को एक बहुत अच्छी सूचना देनी है कि कल यह बिल राज्य सभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ है।

महोदय, यह संविधान संशोधन है और हम जानते हैं कि संविधान संशोधन को पारित करने के लिए कुल सांसदों का 50 प्रतिशत और उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन कल दो तिहाई बहुमत द्वारा नहीं, सर्वसम्मति द्वारा इस बिल को पारित किया गया। एक भी नो नहीं, एक भी ऐब्स्टेनशन नहीं यानी न कोई पीला बटन दबा, न कोई लाल बटन दबा, केवल हरा ही हरा बटन दबाकर के कल लोगों ने इस बिल को पारित किया। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे बांग्लादेश में यह संदेश गया कि जहाँ तक भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे सम्बन्धों का तात्पर्य है, भारत के तमाम राजनैतिक दल एक हैं, उनमें से किसी के अन्दर भी कोई दूसरा रूख नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं आप सबसे भी अनुरोध कर सूँचूँ कि आज जब लोक सभा में यह बिल पारित हो तो जो सद्भावना कल राज्य सभा में दिखाई दी, वही अगर आज यहाँ लोक सभा में भी दिखाई देगी तो बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा शुभ संदेश जाएगा।

महोदय, इस बिल का एक इतिहास है और बहुत संक्षेप में उस इतिहास को आपके सामने रखना चाहूँगी। जिस समय भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, उस समय आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। उस समय एक

रेडविलफ अर्वाइंड हुआ, जिसने भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा तय की, लेकिन वह अर्वाइंड लागू नहीं हो सका। वहाँ 1971 में बांग्लादेश का एक नये राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ और उसमें भारत की जो भूमिका है, वह मुझे आज दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

15.00 hrs.

मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जनरल वी.के.सिंह यहाँ बैठे हैं। वे उस युद्ध में थे। वे आज भी बांग्लादेश में एक मुक्ति योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश का जन्म होने के तीन वहाँ पश्चात् 1974 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और बंग बंधु शेख मुजीबुर्हमान के बीच एक समझौता हुआ जिसे इंदिरा-मुजीब समझौते के नाम से आज तक जाना जाता है। उस समझौते का बांग्लादेश की संसद ने तो अनुमोदन कर दिया लेकिन भारत में उसका अनुमोदन नहीं हुआ। 37 वहाँ तक उस पर किसी तरह की चर्चा भी नहीं हुई। अनुमोदन इसलिए नहीं हुआ कि जमीन पर जो विवादित किया जाना था, वह पूरा नहीं हुआ था।

फिर सन् 2011 में डॉ. मनमोहन सिंह ने पहल की। 2010 में श्रीमती शेख हसीना यहाँ आईं। 2011 में डॉ. मनमोहन सिंह यहाँ गए और वहाँ उन्होंने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। आज यह जो बिल मैं आपके सामने ला रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, यह 1974 के समझौते और 2011 के प्रोटोकॉल की तार्किक परिणति के रूप में आपके सामने रखा गया है। लेकिन जिस समय यह बिल प्रस्तुत हुआ, यह राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ था और मेरे पूर्व मंत्री श्री सलमान सुर्शीद साहब ने इसको रखा था। उस समय राज्य सभा में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और बहुत उग्र विरोध हुआ। तीन पार्टियाँ प्रमुख रूप में इसका विरोध कर रही थीं। एजीपी, बीजेपी और टीएमसी। एजीपी और बीजेपी का मानना था कि इस बिल में असम के दिनों की अनदेखी हुई है। टीएमसी का रोना यह था कि ममता जी को यह लगता था कि इस बिल पर समझौते पर अमल किया जाएगा तो जो लोग आएँगे, वे तो पश्चिम बंगाल में आएँगे, लेकिन पश्चिम बंगाल पर उससे जो भार पड़ेगा, वह वहन करने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है, इसलिए उनसे बात करके वहाँ से यहाँ आने वाले लोगों के लिए वह पैकेज तय होना चाहिए, जिसकी पश्चिम बंगाल को ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए टीएमसी ने विरोध किया और एजीपी तथा बीजेपी ने भी विरोध किया। बिल को स्थायी समिति को रेफर कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देती, लोक सभा भंग हो गई और वह स्थायी समिति भी भंग हो गई। उसके बाद हमारी सरकार 26 मई, 2014 को आई।

मैं सदन को बताना चाहूँगी कि विदेश मंत्री के रूप में जो मेरी पहली विदेश यात्रा हुई, उसके लिए मैंने बांग्लादेश को चुना। जब मैं बांग्लादेश गई, तो वहाँ के सभी राजनेताओं ने, अलग-अलग भी जब वे मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे यही बात की। जब मैं प्रधान मंत्री शेख हसीना जी से मिली तो उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक कहा कि जो प्रोटोकॉल मेरे और डॉ.मनमोहन सिंह के बीच में तय हुआ है, हस्ताक्षरित हुआ है, आप उसको आगे बढ़ाइए। वापस लौटकर मैंने प्रधान मंत्री जी को कहा, तो प्रधान मंत्री जी ने मुझे कहा कि इसमें जो अनसुलझे मुद्दे हैं, यानी जो उलझे हुए मुद्दे हैं, उनको तुम सुलझाओ और आगे बढ़ो।

सबसे पहले हमने ममता जी से बात की। ममता जी से बात करते समय पता चला कि वे एक पैकेज चाहती हैं कि वहाँ से जो लोग आएँगे, उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए जो खर्चा उनको उठाना पड़ेगा। ममता बनर्जी से दो-तीन चक्के बात हुई। ममता बनर्जी ने हमसे 3008 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा जिसके दो भाग थे। एक भाग था जो फिवरड एक्सपेंडीचर होने वाला था और वह फिवरड एक्सपेंडीचर लगभग 775 करोड़ रुपये का था जिसमें कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट और वह एनवतेक्स जिनका इनफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उसके लिए उन्होंने मांगे और 2234 करोड़ रुपये उन्होंने वेरिफेबल मांगे। वेरिफेबल का मतलब था परिवर्तनीय - जो इस बात पर आधारित था कि कितने लोग वहाँ से आएँगे। जब आकलन किया गया कि कितने लोग आएँगे तो एक छोर और दूसरे छोर के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। एक आकलन यह रहा था कि 3500 आएँगे। दूसरा आकलन यह रहा था कि 35000 आएँगे। इसलिए यह जो पैकेज बना, यह 35000 को सामने रखकर बना, कि जितने आएँगे, उसके आधार पर इसको परिवर्तित कर लेंगे, लेकिन यह पैकेज उनका आया।

मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगी भाई शशि थरूर जी का, जो हमारी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने तीन महीने के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट हमको दी। जब नई कमेटीयों गठित हुई तो वह 1 सितम्बर को गठित हुई थीं। 16 सितम्बर को हमने इनको यह बिल रेफर किया और 1 दिसम्बर को उन्होंने हमें रिपोर्ट दे दी। वह सत् 19 दिसम्बर को समाप्त हो गया, करना हमारी कोशिश थी कि हम उसी सत् में इसको लेकर आते। लेकिन शशि जी ने अपनी कमेटी की तरफ से काफी चीजों की हमसे अपेक्षा की थी। उसमें एक चीज यह थी कि यह पैकेज हम तय कर दें। दूसरा था कि वहाँ का तॉ एण्ड ऑर्डर सुरक्षित करने का हम लोग काम करें। ऐसे बहुत से काम थे, जो हमको करने थे, जो हम 19 दिसम्बर तक पूरे नहीं कर सके, लेकिन शशि जी ने मुझसे पूछा कि हमने कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि जल्दी आप इस बिल को लायें तो आप कब लाएँगी। मैंने कहा कि बजट सत् के दूसरे खण्ड में ले आऊँगी, क्योंकि, बजट सत् का पहला खण्ड तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण, रेल बजट और सामान्य बजट में चला जाता है, मैं इसे दूसरे खण्ड में ले आऊँगी। आज मुझे इस बात की सुशी है कि मैं अपना वायदा निभा सकी और शशि जी, यहाँ बजट के दूसरे खण्ड में राज्य सभा से पारित करके इस बिल को मैं यहाँ ले आई।

जैसा मैंने कहा कि 3008 करोड़ का पैकेज ममता जी ने मांगा था, वह हम लोगों ने तय कर दिया तो टी.एम.सी. ने कहा कि हमारे सब मुद्दों का समाधान हो गया है और अब हमें इसमें कोई आपत्ति

नहीं है। ममता जी स्वयं बंगलादेश गईं और उन्होंने वहां भी शेखा हसीना जी से कहा कि मुझे अब इस बिल पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक असम का सवाल था, जब हमने वहां बातचीत करनी शुरू की, इससे पहले कि कोई समझौता होती, वहां के मुख्यमंत्री ने हमारे ही स्वर में स्वर मिलाकर यह बात कही कि हां, असम की तो एक इंच भूमि भी जानी नहीं चाहिए और उस भूमि को हमें लेना चाहिए, तब हमने यह सोचा कि अगर यह बात है कि साया का साया असम आज एक होकर के यह कह रहा है कि उस भूमि को भी वापस लीजिए तो बेहतर यह होगा कि हम असम का हिस्सा इससे अलग रखा करके और पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा वाला हिस्सा हम एल.बी.ए. के शू पारित करवा लें और असम के हिस्से को रीनिगोशिएट कर लें। इसलिए मैं कैबिनेट के पास गईं और वहां से मैंने यह संशोधन करवा लिया कि हम असम को बाहर रखा कर इस बिल को पारित करवा लें। लेकिन जब इसके बाद मैंने सभी पार्टी नेताओं से बातचीत करनी शुरू की, यहां शशि जी से बात की, राज्य सभा के नेता, प्रतिपक्ष गुलाम नबी जी से बात की, उनके उप-नेता आनन्द शर्मा जी से बात की, ममता बनर्जी जी से खुद बात की, सी.पी.एम. के सीताराम येचुरी जी से बात की तो असम पर उनको तो एतराज नहीं था, लेकिन कांग्रेस से मुझे बहुत साफ यह कहा गया कि हमारा समर्थन चाहिए तो असम को इसमें शामिल करो। फिर मैंने बाकी सबसे भी बात की और बैठ करके यह सोचा कि अब मेरे पास दो विकल्प हैं, एक विकल्प है कि मैं एल.बी.ए. को छोड़ दूँ और दूसरा विकल्प है कि मैं असम को शामिल करके आगे बढ़ूँ। आज मैं यहां कहना चाहूंगी कि एल.बी.ए. को छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं होती और इसीलिए सब की सहमति बन जाये, इस कारण से हमने यह निर्णय किया कि हम असम को भी इसमें शामिल करके एल.बी.ए. को वैसे ही पारित कराएंगे, जैसा 2013 में रखा गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, दोबारा हम लोगों ने कैबिनेट की बैठक की और उस कैबिनेट में से जो संशोधन हमने पहले तय किये थे, वह छोड़कर हमने तय किया कि सब को साथ लेकर ही हम इस बिल को लाएंगे। फिर मैंने संशोधित तरीके से बिल वहां पेश किया, जो संशोधन राज्य सभा में पेश किये थे, उनको मूत नहीं किया और यह बिल 2013 में जिस तरह से प्रस्तुत हुआ था, बिल्कुल उसी रूप में राज्य सभा से पारित करवाया और उसी रूप में यहां लोक सभा में लेकर आई हूँ।

मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बिल से तीन बड़े लाभ हो रहे हैं। एक तो अनडिमाकैटेड बाउण्ड्री थी, यानि जिस भूमि का सीमांकन नहीं हुआ था, वह बाउंड्री डिमाकैट हो जायेगी, सीमांकित हो जायेगी। दूसरे जो एन्वेलोप्ड हैं, उनमें रहने वाले लोगों का जो भाग्य अघर में लटकता हुआ था, वह भाग्य सुनिश्चित हो जायेगा। तीसरा, एडवर्स प्रजेसन, यानि अनधिकृत कब्जा जिन दोनों देशों का जिस-जिस जमीन पर था, वह अधिकृत इसके अनुसार जो किया गया है, वह अधिकृत हो जायेगा। इन तीन चीजों के बाद हम उनसे ट्रांजिट, ट्रेड, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं और जो हमारा नोर्थ ईस्ट है, वह हमारे और ज्यादा करीब आ सकता है और बंगलादेश के साथ आज हमारे रिश्ते, आज मैं यहां कहना चाहूंगी, उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, जिस पर 1971 में पहुंचे थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, 41 वर्षों बाद वह समझौता इस बिल को पारित होने के बाद आज आकार लेगा और यह सौवां संशोधन होगा। आपने देखा होगा कि जैसे पहला संशोधन इतिहास में दर्ज होता है, उसी तरह से सौवां भी इतिहास में दर्ज होता है तो यह सौवां संशोधन इतिहास में दर्ज हो जायेगा।

मैं इतनी बात कहते हुए इस बिल को चर्चा के लिए रखती हूँ। चर्चा में जो मुद्दे उठेंगे, उनका जवाब मैं उत्तर देते समय दूंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस बिल को चर्चा के लिए प्रस्तुत करें, धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India to give effect to the acquiring of territories by India and transfer of certain territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the Governments of India and Bangladesh, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहामपुर) : मैडम सुआमा स्वराज जी मीठी-मीठी बातें बोलने में सारे हिन्दुस्तान में माहिर हैं। बड़ी अच्छी बातें आप कहती हैं, वह सब को जानकारी है। आपको मैं याद दिला दूँ कि आजादी के बाद सबसे पहले 1958 में नेहरू-नूज एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद इंदिरा-मुजीब और उसके बाद मनमोहन सिंह-शेखा हसीना पैक्ट हुआ। इन तीनों की परंपरा शायद आपको मालूम है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि माननीय सुआमा स्वराज जी ने आज किस तरह इस हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है। यह जो आपने कहा कि हम सबको हरा बटन दबाना चाहिए, तो हम सब हरा बटन दबाना चाहते हैं। मैं खुद पश्चिम बंगाल से आता हूँ। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकगत एक आत्मा की तरह है। आप शायद यह जानकर खुश होंगे कि एक ही कवि स्वीनूनाथ टैगोर ने बांग्लादेश और हिन्दुस्तान, दोनों देशों के नेशनल एंथेम की रचना की है।

15.11 hrs. (Shri Ramen Deka in the Chair)

बांग्लादेश के साथ हमारा इमोजनल अटैचमेंट है, हमारा कल्चरल अटैचमेंट है। हमारा फीचर, हमारी लैंग्वेज, हमारा खान-पान सब एक है। इसलिए जब बांग्लादेश की बात आती है तो बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय के हम सब लोगों के अन्दर एक इमोजनल अटैचमेंट पैदा होता है।

Madam Sushma Swaraj, just listen to me. It was stated that : "This land swap issue is under the Ministry of External Affairs." But a few weeks ago, the Minister of State for Home Affairs, Shri Kiren Rijiju, said in New Delhi that : "The Constitution (Amendment) Bill to ratify the Indo-Bangladesh LBA is likely to be introduced with a major change by de-linking Assam." यह ऑन-रिकॉर्ड है।

The Union Minister of State for Sports, Shri Sarbananda Sonowal, defended the Government's decision to de-link Assam from the Bill. He said that : "This was not a political decision. This is a decision honouring the wishes of the people of Assam. At this moment, the people of Assam do not want to give their land to Bangladesh." यहां आप कहते हैं कि ए.जी.पी., बी.जे.पी. और तृणमूल कांग्रेस - हम सब एक हो गए और इसलिए हम यह बिल ला रहे हैं।... (व्यवधान) आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।... (व्यवधान)

श्रीमती सुआमा स्वराज : अधीर रंजन जी, मुझे नहीं मालूम कि जब मैंने सदन में इसके बारे में बोला, उस समय आप सदन में बैठे थे या नहीं। लेकिन, जो बात आप कह रहे हैं, वह तो मैंने शब्दशः वाती है। आप कौन-सी चीज कह रहे हैं कि कौन एक हो गया?

खड़के जी, आप तो यहां थे, जब मैंने बोलना शुरू किया था। शशि जी कहां गए? ये सारी बातें, जो अधीर रंजन जी कह रहे हैं, वह मैंने खुद बोली है। श्री किरें रिजिजू और श्री सर्वानन्द सोनोवाल की बात जो आप कह रहे हैं, उसके बारे में मैंने खुद बोला है कि जब यह बिल प्रस्तुत हुआ था तो हमने विरोध किया था। हमने इसका विरोध क्यों किया था, मैंने यह भी बताया। उसके बाद हम असम को छोड़ कर इस बिल को लाना चाहते थे, हमने यह भी बताया। अब असम को शामिल करके ला रहे हैं, यह भी बताया। वया आप उस समय इस हाउस में नहीं थे या आपने अपना भाआण पहले से तैयार कर लिया है कि मैं जो भी बोलूँ, आपको यही बोलना है? ऐसा लग रहा है।

सभापति जी, ऐसा लग रहा है कि मैं वया बोलूंगी, इसके बारे में बिना सोचे इन्होंने अपना भाआण तैयार कर लिया है और बिना मेरी बात सुने ये वह ही बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

अधीर रंजन जी, जो आप कह रहे हैं, वह तो मैं सब कह चुकी हूँ। मैंने बहुत पारदर्शिता से अपनी बात रखी है।... (व्यवधान) मैंने इतनी पारदर्शिता से अपनी बात रखी है कि हम असम को छोड़ कर इस बिल को ला रहे थे। लेकिन, जब प्रमुख प्रतिपक्षी दल से बात हुई, बाकी लोगों से बात हुई तो हमको यह लगा कि असम को साथ लेकर हमें यह बिल लाना चाहिए। मैंने तो यहां तक कहा कि हम पूरा एल.बी.ए. बिल को रोक कर रखते तो यह बुद्धिमत्ता नहीं होती। इसलिए हमने असम को साथ में लेकर इसे करने की बात की। एक भी बात ऐसी नहीं है, जिसे आपने कहा और मैंने वह बात न बोली हो। आप यह पहले से तय हुआ भाआण छोड़ दीजिए और जो मैंने बोला है, आप उस पर बोलिए। मैंने कोई गुमराह करने वाली बात नहीं कही है। जो आप बोल रहे हैं, मैं वह सब बोल चुकी हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं आप जैसा विद्वान नहीं हूँ, इसलिए मजबूरन थोड़ा पढ़ा-लिखा भाआण देना पड़ता है। मैडम सुआमा स्वराज जी, अगर असम को डीलिक करने का प्रयास नहीं होता तो आज कांग्रेस पार्टी के साथ यह बिल लाने के लिए एनडीए को सलाह-मशविरा करने की कोई जरूरत नहीं होती।... (व्यवधान)

Please listen to me. The Chief Minister of Assam, Shri Tarun Gogoi, requested the Prime Minister, Shri Narendra Modi, for inclusion of the State of

Assam in the Protocol signed between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh in September, 2011. The Chief Minister, Shri Tarun Gogoi, expressed surprise at the reported decision of the Government of India not to include clauses relating to Assam sector in the Protocol ratified by the Parliament. The Government of India did not hold any consultation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप असम को बाहर रखकर यह करना चाहते थे, क्योंकि असम में इलेक्शन था। ... (व्यवधान) असम का बीजेपी पार्टी का जो संघ परिवार है, वह नहीं चाहता था कि असम को इसमें लिंक किया जाए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। इसलिए नरेन्द्र मोदी जी को खुद वहां जाकर संघ परिवार के लोगों को समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एल.बी.ए. को पारित करना चाहिए। इसीलिए एल.बी.ए. को लाने में इतनी देर हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि वहाँ 2011 में सतमान खुर्शीद जी इसे लाए। ... (व्यवधान)

The Constitution (Amendment) Bill, 2013 was introduced in the Rajya Sabha in December, 2013 by Shri Salman Khurshid, Minister of External Affairs. It was referred to the Parliamentary Standing Committee, and Madam also referred to it. The India-Bangladesh Agreement was signed in 1974, but as it was not ratified, it has not been implemented in reality.

Bangladesh is our immediate neighbour. One may divorce one's wife, but one cannot divorce one's neighbour. That is why the Land Boundary Agreement is aimed to enhance bilateral cooperation between the two countries. This is a momentous legislation and when I am participating in the debate, I am feeling ecstatic and greatly elevated. The historic agreement will contribute to a stable and peaceful boundary and create an environment conducive to enhanced bilateral cooperation. It will result in better management and coordination of borders and strengthen our ability to deal with smuggling, illegal activities and other trans-border crimes.

In 2011, the Protocol has been prepared with the full support and concurrence of the State Governments concerned, that is, Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal. Now, under no circumstances, we should leave the arena whereby India's image could be tarnished as a non-credible country in the comity of nations.

Three issues were outstanding between Bangladesh and India. One is the un-demarcated land boundary of 6.1 kilometres; exchange of enclaves and adverse possessions remain unsettled. The truth is that I am very much in agreement with the concern expressed by the Chief Minister, West Bengal because the Radcliff dispensation which can be considered as a colonial hangover is still haunting us. As per the Radcliff dispensation, the line was drawn arbitrarily much to the disservice of the neighbouring and adjoining States of Bangladesh, namely, West Bengal, Meghalaya, Assam and Tripura. Therefore, I would be in full support of the rehabilitation package that has been sought by the West Bengal Government. Not only that. I would also propose that rehabilitation should be proper and should be scientific. The rehabilitation has to be a decent one and a BPL-like package. The Indian citizens residing in Indian enclaves in Bangladesh have been deprived of basic necessities and rights since 1950. They deserve a decent rehabilitation package once they come to mainland.

It is essential to have a seamless integration of Bangladeshi enclaves with the local area and population. For achieving this, the physical and social infrastructure of these enclaves has to be upgraded to the level of neighbouring areas. It is essential that such movement and rehabilitation of population from Indian enclaves in Bangladesh and Bangladeshi enclaves being transferred to India does not lead to local resentment and social tensions. That is why, I would propose that at the time of entry, the person would be provided biometric Adhaar card and his name would be entered in the National Population Register. Secondly, the families should be housed in temporary relief camps in predetermined locations preferably in the same police stations in which their original enclaves were located. This PS-wise relocation would be better due to presence of large number of rivers in the district and geographical contiguity would make assimilation faster. The family members should also be issued EPI card, BPL ration card and job card under MNERGA. Bank accounts should also be opened under Jan Dhan Yojana.

I am feeling proud that I have been able to participate in this historic legislation. Again, I would remind the hon. External Affairs Minister that her Government was suffering from some sort of hiccups. Their Government was posing flip and flop. कभी 'हां' और कभी 'न' की सरकार को यह सोचना चाहिए कि 'हां' और 'न' की बात हर वक्त नहीं चलती है। आज 'हां', कल 'न' को छोड़ें, हर वक्त 'हां' को 'हां' कहें और 'न' को 'न' कहें। धन्यवाद।

*SHRI S.S.AHLUWALIA (DARJEELING): Respected Chairman Sir, today the Constitution (One Hundred and Nineteenth) Amendment Bill 2013, has been presented to this august House to ratify India. Bangladesh Land Boundary Agreement and I take the floor to support and say a few words about this legislation. I am speaking in Bengali particularly because lakhs of people in both sides of the border are waiting for this historic event. They wish to know what the Indian Parliament is going to do today and must be glued to radio or television sets. Therefore I will deliver my speech in Bengali. At the very outset, I want to make it clear that if anyone tries to snatch even an iota of land forcefully from us, then our security forces can go to any extent, even sacrifice their lives to save their motherland and this is true for both India and Bangladesh. But I can recall what our erstwhile Prime Minister Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee had said during his Lahore trip. He had said, "We can change history, but not geography. We can change our friends but not our neighbours" It means that if we have sour relationship with Pakistan or Bangladesh, it is possible to change the bitter history with love and peace. But if we want to push our neighbours back or change the geography, it will not be feasible. Thus, our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and our respected Minister of External Affairs Smt. Sushma Swaraj ji are trying to follow Atalji's footsteps. We could have said that this is the treaty of Shri Manmohan Singh and Sheikh Hasina and we have no role in it. But we did not say that. We had to realise the vision of Shri Vajpayee ji and so we shouldered this responsibility. Thus I stand here to support this Bill.

My previous Speaker, Shri Adhir Ranjan Chowdhury hails from Murshidabad. I don't know whether any part of his district is linked with Bangladesh or not. But I have been elected from such an area a portion of which is connected to Bangladesh border. When I visit that part, my mobile catches the signals of Bangladesh and I have to receive Indian calls through Bangladesh towers. Thus I can feel their pain. When the Radcliffe Award was signed, it was

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

decided that a 4096 km long boundary will be drawn between India and East Pakistan. Out of that 262 km stretch would be with Assam, 856 km with Tripura, 318 km with Mizoram, 433 km with Meghalaya and 2217 km long boundary would be drawn with West Bengal. However complete demarcation could not be done and problems cropped up in those enclaves where Indians and Bangladeshis were scattered. Many attempts were made to solve these problems but to no avail. In December 1949, an Indo-Pakistan Boundary Dispute Tribunal was set up under the Chairmanship of

a Swedish Supreme Court Member Albott Bagge, former member of Supreme Court of Sweden. A representative each from India and Pakistan was also present. But no solution could be found. Thereafter on September 10, 1958 the Nehru-Noon pact was signed. Immediately after that, the Berubari issue erupted and Hon'ble President referred the case to the Supreme Court. So the progress was halted to some extent. I can still recall what happened at that time. On December 16, 1971, 90,000 Pak soldiers were made to surrender – before General Jagjit Singh Arora. Those 90,000 soldiers led by General Niaji used to brutally torture the innocent people of East Pakistan who were fighting for their rights, for freedom under the leadership of Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman. About 3 lakh people were killed in Bangladesh. The then Prime Minister dispatched Indian troops to East Pakistan to save the neighbours and Jagjit Singh led the contingent. It was a short duration battle and within 13 days, 90,000 soldiers were compelled to surrender. I can visualize the day when they were being taken as hostage. I was a young man of 20 years at that time. I was studying in the university. When Bangabondhu Mujibur Rahman was arrested and taken to Lahore, people of Bangladesh were wailing and lamenting. Lakhs of people became homeless and they came to Kolkata as refugees. In University of Calcutta, I was into student politics and a member of Chhatra Parishad. We set up camps for the refugees and received them, provided shelter, medical aid and food. I can still remember the pathetic scenes. The day when Bangabondhu was released from Lahore prison on 8th January and was brought to Delhi airport, he was received by the then President Shri V.V.Giri, Prime Minister Smt. Indira Gandhi and the entire cabinet. Then he was sent to Dhaka by RAF aircraft. After that, the 1974 friendship pact was signed. Why this month of May is so important? What is the significance of this month and why are we eager to pass this legislation urgently? It is because on 16th May 1974, Indira-Mujib Treaty was signed in Delhi. The Parliament of India is trying to ratify the pact after so many years by passing this Bill. But why did it take so long? The reason is, after 1974 a combat committee was set up in Kuchlibari. In Dahagram and Angrapota, a movement was organized. In 1992 Teenbigha Agreement was signed. But this movement claimed three lives and many persons were displaced and also put behind bars. They struggled hard for their own rights. Even today, their only demand is that Dahagram and Angrapota should remain a part of India while the Teenbigha corridor should be abolished. I don't know whether the Government of India will consider this or not. But today in the interest of West Bengal and the entire country, when we are going to usher in a new era by ratifying the Indira-Mujib Pact as well as the treaty signed by Shri Manmohan Singh and Sheikh Hasina on 6th September 2011, we must look into every aspect. By the way, Sheikh Hasina is the daughter of Mujibur Rahman.

The issues with Bangladesh will not be resolved only by acknowledging this treaty. In order to have more cordial and warm relationship with Bangladesh, we need more development in that country.

If someone asks why the people of East Pakistan wanted to have an independent country, the answer is that all their revenue earnings from jute cultivation and jute industries were diverted to West Pakistan which in turn used to spend it for defence expenditures. People demanded that the money should be spent for the development of East Pakistan, to build road, rail infrastructures, to build dams, to set up factories and industries so that the Bengali people of the region are able to live with dignity and rights. Moreover the language of Urdu was imposed upon them forcefully. The mother tongue of the people of Bangladesh, cutting across religions lines, is Bengali. If something was done for Bengali language, it was mostly by the people of East Pakistan who struggled to establish the supremacy of the Bengali language. They fought to get the national language status for Bengali. These were the two main issues – one, development and two, language. They were deprived of both. Therefore they had to struggle and fight against West Pakistan. Sheikh Mujibur Rahman was imprisoned twice for leading the movement. He fought for the development of Bengali community; he fought for the language of Bengali. People of that country whole-heartedly supported him and took the movement forward, resulting in the creation of an independent nation called Bangladesh. Today their dreams are going to become a reality; today the dream of Sheikh Mujib is going to become a reality; today the vision of the Indira – Mujib treaty is going to be realized; today the goal of Manmohan Singh and Sheikh Hasina is going to be achieved. People of India and Bangladesh want to see development in both the sides of Padma. They want jobs for the jobless, education for the illiterates, food for the hapless. People want freedom from poverty. Thus I also have some demands to put forth. Firstly, we need access to road. The entire North Eastern region has to take a detour via Siliguri. But if we go through Dhaka then it can be shorter. If we need to go to Agartala, we have to go via Silchar. But if we can pass through Dhaka, it can be easier for us. Thus I demand the road access, rail access and river access or sea link. I hope that the Government will definitely sign some more pacts to this effect after the passage of this Bill. I have been receiving many telephone calls for the last few days from Bangladesh and India and people are informing me that tension is brewing in places. The opposition forces in both the countries are active and contemplating communal riots; rapes, various anti-social activities etc. may take place after swapping of land or enclaves. Therefore immediately the military of both the countries should come together to build a coordination force to thwart any untoward incident that might take place.

We are making promises that whoever will come from the other side of the boundary will be given Indian citizenship but I demand that not only citizenship, but all other rights and facilities like Aadhar card, Voter card Gas connection, and the new insurance scheme which is going to be launched by Hon'ble Prime Minister tomorrow should be extended to them along with zero balance account facility, Jan Dhan account, educational rights, infrastructure etc. so that they can say with pride that we are no longer subjugated, we are free, and independent Indians and the people of Bangladesh can say that we are free Bangladeshis.

We think in Bengali, we speak in Bengali, we love Bengali. Therefore I wanted to express my views in Bengali. I recall, "I was born in Bengal as a Bengali, I think in Bengali, speak in Bengali, I segregate in Bengali and again join hands to unite Bengal". Ganga is my mother, Padma is also my mother; Meghna and Yamuna are the tears flowing down my two eyes. The sky is the same, the air is the same, the expressions of joy and sorrow are the same, the music of the chirping of Doel and Koel birds is the same. Today while supporting this legislation, I can just say that my predecessors were also displaced from Sialkot but I was born in Bengal. Where is Sialkot and where is Bengal, my birthplace; from the land of Iqbal to the land of poet Nazrul. Nazrul was from Burdwan and Kabiguru Rabindranath Tagore was from neighbouring Birbhum. I was born and brought up in this holy land of Nazrul Islam and Tagore. I pay my respects to the people of Bangladesh.

While supporting this Bill, I reiterate my demand that Dahagram and Angrapote should remain a part of India and Teenbigha corridor should be done away with. A new Tetulia corridor should be created because if I need to go to Teesta point from Dashpara-Chopra via Siliguri, the distance is 117 km but if we use Tetulia corridor it comes down to 26 kms. There was a corridor from Mathabhangra to Mekhligang which was called the Immigration corridor. If that is made functional then the distance will be reduced to 26 km from 56 km. This should be considered for the benefit of the people. The Bangla bandh border that has been opened near Siliguri and Jalpaiguri should be made operational.

Berlin wall has been demolished and Europe has become one. If similar sentiments of peace and love for each other are spread amongst the South-East Asian countries, then we can have more cordial relations with all. With this hope I thank you and conclude my speech.

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Sir, I rise to participate in the discussion and support the Constitution (119th Amendment) Bill, 2013.

This Bill has been brought forward to give effect to acquiring of territories by India and transfer of certain territories to Bangladesh, in pursuance of the agreement signed between India and Bangladesh in May 1974 relating to the demarcation of the land boundary and also subsequent protocol signed in September, 2011.

India and Bangladesh have a common land boundary of approximately 4097 kilometres. This land boundary was determined as per the Radcliffe Award of 1947. Some provisions of this Award led to disputes which were sought to be resolved through the Bagge Award of 1950. This was the first effort made to settle the disputes.

The second effort made was through Jawaharlal Nehru-Feroz Khan Noon Agreement of 1958. One of the issues in this Agreement, namely, the division of Berubari Union was referred to the Supreme Court for an advisory opinion by the President under article 143 (1) of the Constitution. To comply with the opinion rendered by the Supreme Court, the 9th Constitutional Amendment Act was introduced in 1960. But due to litigation and other problems, this 9th Constitutional Amendment Act could not be notified in respect of territories in the former East Pakistan or the present Bangladesh.

Likewise, several efforts were made to resolve these disputes during the course of the last more than 60 years. But they could not see the light of the day.

The present Constitutional (Amendment) Bill legalizes the Agreement entered into between India and Bangladesh in 1974 and the Protocol entered into in 2011. The Government has also stated that the State Governments concerned, namely, the Governments of Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal were closely associated during the process of demarcation of un-demarcated boundary, and during the process of determination of territories in adverse possession and exchange of enclaves.

We urge upon the Government of India that it may continuously engage in dialogue and mutual consultation with the State Governments concerned when the Agreement is actually implemented on the ground. It is an appreciable thing. This is correct. I am from Tamil Nadu and I feel this is correct.

At this juncture, we would like to draw a parallel to the ceding of Katchatheevu to Sri Lanka without the approval of Parliament by means of a constitutional amendment. This has very seriously affected the livelihood of the fishermen of Tamil Nadu who are Indian citizens.

The ceding of Katchatheevu is in total violation of the constitutional provisions and also the views given by the Supreme Court of India in a Presidential Reference made in the Berubari case.

This is why, our revered leader and people's Chief Minister Makkalin Mudhalvar, Dr. Amma had filed a case in 2008 in the Supreme Court against ceding of Katchatheevu in her personal capacity as the General Secretary of our Party, AIADMK. Subsequently, in the year 2011, the Government of Tamil Nadu impleaded itself, as a party, in this case, since the State is the custodian of all land records. This case is still pending in the Supreme Court of India. To go back slightly into the history of Katchatheevu, I would say that this Islet was originally owned by the Ramnad Kingdom of Ramanathapuram district of Tamil Nadu before Indian Independence. This Islet was historically a part of the Ramnad Raja's Zamindari and later became a part of the Madras Presidency. This Islet was always of strategic importance and special significance for fishing operations in the area.

So, from times immemorial, this Islet was a part of Indian territory, but due to the agreement in 1974, this was a bad agreement for us, this Islet was ceded to Sri Lanka which is the root cause for the problems of the fishermen that we are facing every day in the Palk Strait. It is again unconstitutional because this part of the Indian territory was ceded to Sri Lanka without the approval of the Indian Parliament by means of a constitutional amendment. The ceding of Katchatheevu is illegal because no constitutional amendment was approved by the Indian Parliament.

Secondly, in Katchatheevu, there is a St. Antony's church having more than 150 years of rich tradition. This church conducts annual car festival which runs for three days in a year. This holy place is visited and worshipped by people belonging to all religions – be it Christians, or Hindus – from both the countries during this annual festival. You will be surprised to know that this church was built by an Indian Catholic, who is a Tamilian, named Srinivasa Padaiyachi. This goes beyond doubt that this Islet belongs to Tamil Nadu and it is a territory of India.

But presently because of conflicts, Indian Tamil people are not allowed to go and worship in that church. Even if they go, they are scared away by the Sri Lankan Navy officials. It is a disrespect shown to the religion and to the religious festivities. Hence, I would like to request the Government to see that at least during the three-day annual festival of the Church, the security personnel from the two nations are present there to safeguard the interests of the Indian Tamil people going there to attend the festivities.

Due to all these disturbances and troubles being created by Sri Lanka, I would like to urge upon the Government of India to rescind the agreement with Sri Lanka that was entered into in 1974 and restore the rights over that Islet to India so that fishermen from Tamil Nadu could fearlessly go and fish in the traditional waters.

15.59 hrs (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Sir, coming back to the present Bill, I would say that the Bill does not provide for suitable rehabilitation and compensation measures for the people

who will be returning from the Indian enclaves in Bangladesh. I would like to urge upon the Government that it may seriously address this issue and provide an acceptable package of rehabilitation to the people who will be returning to India. I would also like to urge upon this House to bring a similar constitution amendment Bill to bring back Katchatheevu Islet back to India.

In the same way, the Government of India should also take adequate steps to safeguard the interest of the Indian nationals who would be staying back in Bangladesh enclaves and facilitate them to acquire Bangladesh citizenship and all other attendant benefits.

With these words, I support the Bill and thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, यह विचारणीय सीमा तक ही सीमित नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण बहस है, मैं विदेश मंत्री जी से कहूँगा कि हमारी बात को गंभीरता से लीजिए। अब आप महासंघ बनाने का प्रयास कीजिए, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों को मिलाकर महासंघ बनाने की बात कीजिए। इस संबंध में समाजवादी पार्टी लगातार भाषणों में और इस सदन में बोलती रही है। इन तीनों देशों का महासंघ अगर सरकार बना दे तो आपका इतिहास बन जाएगा, तीनों देश व्यापार के मामले में सम्पन्न हो जाएंगे। खेल के मामले में दुनिया कोई हमसे नहीं जीतेगा। अगर भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों में एक होकर खेलेंगी तो क्या कोई उसे हरा सकेगा। इसीलिए हम आपसे चाहते हैं कि सीमा तक ही बात सीमित मत रखिए, यह बिल अच्छा है, सीमा का विवाद सुलझाने का हम स्वागत करते हैं। आडवाणी साहब, आपसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आप कोशिश कीजिए महासंघ बनाने की, आप हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों को मिलाकर महासंघ बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा होने से तीनों देशों के बीच विवाद खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, सम्पन्नता आएगी, अना-जाना बढ़ेगा और तीनों देशों में व्यापार बढ़ेगा। आडवाणी साहब से मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। महासंघ बनाने के लिए कोशिश कीजिए। सीमा के बारे में यह बात अच्छी है, हम इसका समर्थन करते हैं, धीरे-धीरे सीमा सुलझ जाएगी तो आप महासंघ के लिए आगे बढ़िए। महासंघ के लिए प्रयास करिए। बांग्लादेश बनाने में हिन्दुस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है, इस अवसर पर हम विशेषकर अरुंधती जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ काम किया था। इसीलिए पाकिस्तान टूटा और उससे आपका कद बढ़ा और आपकी बहुत सी समस्याएँ हल हो गयीं, वरना उधर बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान, जब दोनों एक साथ थे, हमारे लिए समस्या बहुत गंभीर थी। उस समय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात के लिए प्रयास किया था और तीनों देशों के लोगों से बात भी की थी। मैं आज यह बता रहा हूँ, सत्ता में बैठे लोग महासंघ नहीं चाहते, लेकिन जनता चाहती है। पाकिस्तान के लोगों से मेशी बात हुई। अलीगढ़ में एक शादी में पाकिस्तान से लोग आए थे, उन लोगों ने अपने आप कहा, साहब, जैसा आप बोलते हैं, अगर महासंघ बन जाए तो इससे बेहतर और कुछ हमारे लिए नहीं है। महासंघ बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसमें हमारा पूरा सहयोग है। हम जानते हैं कि पूरा सदन सहयोग करेगा कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का महासंघ बने, जिससे तीनों का व्यापार, खेल बढ़ेगा। अगर कुछ और नहीं तो खेल से ही शुरूआत कीजिए। धीरे-धीरे अगर यह महासंघ बनेगा तो हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे मजबूत देश बनेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनेंगे, इससे हिन्दुस्तान मजबूत बनेगा। बांग्लादेश में आपके कितने लोग हैं, किसी तरह से ज्योति बसु यहां आ गए, वह भी बांग्लादेश के थे, वह इधर आ गए छोड़कर बांग्लादेश। इस बात को सदन गंभीरता से ले और इसके लिए हिन्दुस्तान को प्रयास करना होगा। आज जो बहस हो रही है, वह अच्छी बहस है। सीमा की बात ठीक है, जब सीमा का मामला सुलझेगा तो अच्छे संबंध बनेंगे। इसलिए हमारी अपील है कि इस संबंध में आडवाणी जी, आप अपनी पार्टी में प्रयास कीजिए। हमारी पार्टी सहमत है, सारे लोग सहमत हैं और पाकिस्तान में हमने अपना जो प्रतिनिधि भेजा, वहां की जनता ने माना, लेकिन जो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में सत्ता में बैठे होंगे, वे इसके लिए तैयार नहीं होंगे। यहां भी सत्ता में लोग बैठे हैं, मोदी साहब हैं, आडवाणी जी सत्ता में ही हैं, विदेश मंत्री जी बैठी हैं, वह समझ रही हैं। आपको तालच नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि सत्ता में बैठे लोग इसे नहीं होने दे रहे हैं, पाकिस्तान में सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वे नहीं होने दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वे नहीं होने दे रहे हैं, जिसने ऐसा करने का प्रयास किया था, उसकी हत्या कर दी गयी। बांग्लादेश बनाने में आपके कितने लोग शहीद हुए, सेना के कितने लोग शहीद हुए हैं तब बांग्लादेश बना, तब पाकिस्तान टूटा।

16.00 hrs.

आज इस अवसर पर मैं विदेश नीति के संदर्भ में इंदिरा जी की तारीफ करता हूँ और सयहना करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश बनवाया। उसी का नतीजा है कि हमारी बहुत सी समस्याएँ हल हुई हैं। इसलिए आडवाणी साहब भले ही आप सरकार में मंत्री न बने हों, लेकिन आप पहल करें और यहां पर विदेश मंत्री जी बैठी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप पहल कीजिए। हम भी प्रधान मंत्री जी से मिलेंगे और इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। इसलिए आप प्रयास करें एक महासंघ के गठन का, यही हमारे देश और तीनों देशों के हित में है। आज हमारी सीमा पर रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, यह सब खत्म हो जाएगा और देश के लोग देश के विकास में जुटेंगे।

इन्हें शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support, on my own behalf and on behalf of the All-India Trinamool Congress, the One Hundred and Nineteenth Constitution (Amendment) Bill which, after an amendment is passed, will become the One Hundredth Constitution (Amendment).

At the outset, I would like to congratulate our hon. Minister of External Affairs for bringing forward this historic legislation before this House and also for making a statesmanlike speech in opening this discussion and debate.

Our External Affairs Minister referred to the Radcliffe Award of 1947. The roots of the problem that we are going to solve in this Parliament later today go back to the tragic partition of 1947. The irony of that partition was captured best by the Poet W.H. Auden in his Poem "Partition" where he wrote about Radcliff. This is what he had said:

"Unbiased at least he was when he arrived on his mission,
Having never set eyes on this land he was called to partition.

'Time' they had briefed him in London, 'is short. It's too late
For mutual reconciliation or rational debate:
The only solution now lies in separation.

He got down to work, to the task of settling the fate of millions.
The maps at his disposal were out of date
And the Census Returns almost certainly incorrect.
But there was no time to check them, no time to inspect
Contested areas. The weather was frightfully hot
And a bout of dysentery kept him constantly on the trot.

But in seven weeks it was done, the frontiers decided,
A continent for better or worse divided.

The next day he sailed for England, where he quickly forgot
The case, as a good lawyer must. Return he would not,
Afraid, as he told his club, that he might get shot. "

Radcliffe was not a good surgeon. Partition was often referred to as a surgical operation. Not only did he bring misery to the people on either side of the lines that were drawn in 1947 but like any bad surgeon, he left swabs inside the patient. These were the Enclaves that are going to be exchanged today. We call these *Chhit Mahal* in the local parlance in West Bengal.

As I speak today, my mind goes back to 1971 a date to conjure with in South Asian History. I was merely a high school student, not even in college. I used to go with my Paediatrician father Dr. Sisir Kumar Bose to the Bongaon border where millions of refugees had come from what was then the Eastern Wing of Pakistan. I had seen poverty in Kolkata. But I have never seen the kind of human misery that I witnessed in 1971 in the refugee camps around the Bongaon town. But there was something else. I also used to visit the Netaji Field Hospital in a village called Bakchara where the brave, wounded soldiers of Bangladesh's Mukti Bahini used to be brought across the border and public spirited doctors and surgeons from Kolkata would operate upon them. That is the only time in my life that I have seen operations being conducted in the open and there was not even any saline. I have seen Daber Jal, coconut water being used in place of saline. These *Mukti Yodhas* sacrificed there all. Our Indian soldiers made huge sacrifices. What we witnessed in 1971 was a glorious freedom struggle against one of the most brutal military crackdowns in modern history. After the victory of 16th December, 1971, Sheikh Mujibur Rahman, Bango Bondhu came back, and I remember on the 17th of January, my father met him in Dhaka. What was the border like? He just drove across in an ambulance carrying medical supplies for newly independent Bangladesh. That was the kind of border we saw in 1971. People wanting to help each other to live a life of dignity.

Then, of course, in 1974, our External Affairs Minister has referred to the historic agreement made between Bango Bondhu, Sheikh Mujibur Rahman and our great Prime Minister, Indira Gandhi. It is a pity that 41 years have passed before this Parliament could ratify that agreement. Today, the words of Bango Bondhu, his historic speech on the 7th of March are ringing in my ears, when he said,

"Rakte jakham diyeehhi, rekta aro debo edeshea mukte koinye enhanbo, inshallah."

"Since we have given blood, we will give more of it, *Inshallah*, we will free the people of this land." In other words, he offered to give more sacrifice in blood so that the people of East Bengal could be free. He brought freedom to the people of Bangladesh.

We have to look at this 1974 Agreement and the protocol signed in 2011 between the Prime Minister, Manmohan Singh and the Prime Minister, Sheikh Hasina. I had the privilege of meeting the Prime Minister when they gave an award to my father, posthumously just two years ago. I find this is what is really historic and what is really positive about this Bill that has been brought by this Government. We have a carefully balanced Bill; we are protecting and promoting the national interest, the States interest, and the human interest. The national interest, because this Bill, once it is passed later today by this House, will bring about a revolutionary transformation in the relations between India and Bangladesh. I agree with the External Affairs Minister that we will be able to rekindle the spirit of 1971. After that, when you go to ask the people of Bangladesh and the Government of Bangladesh for trade and transit facilities, they will respond to you in a positive manner, So that national interest has been supreme. I know, earlier this week, there was a little temptation to falling prey to the narrow party-partisan interests but what is important today is that the people of Assam also rose to the occasion and the temptation was resisted. National interest was put above party-political interests.

Secondly, States' interests have been protected. It was a real privilege for me to work on the Standing Committee on External Affairs with Dr. Shashi Tharoor of the Congress, Mohd. Salim of the CPI(M), my own colleague, Mumtaz Shangomitra of the Trinamool Congress and so many of the BJP Members and the Members of the other Parties belonging to the ruling coalition. It shows the value of the Standing Committee system in our parliamentary democracy. In the unanimous Report that we tabled in this House on the 1st of December, 2014, we protected the States interests. This is what we said about the earlier history. We said, closer consultations at the highest political level between the Central Government and State Governments would have been desirable. The Committee while appreciating the efforts to keep the State Governments on board, would therefore suggest the Government to effectively coordinate with them on all matters and resolve the lacunae if any relating to the actual implementation of the Accord on the ground.

I am very glad, I am truly happy, I have to tell the External Affairs Minister that she has conducted consultations at the highest political level as we had wanted, she has spoken several times with our leader, the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. We had also said, the Committee expects that the Central Government and the State Government of West Bengal will arrive at a consensus on the issue relating to the rehabilitation package. All the humanitarian issues should be resolved in advance including assistance from the Central Government in this regard.

I trust, as the External Affairs Minister has assured on the floor of this House that the rehabilitation package which has been sent to her by the Government of West Bengal led by the Chief Minister Mamata Banerjee on the 6th of December, 2014 will be available to the State so that we can build infrastructure and also give a true life of dignity to those in the enclaves who have been leading a miserable existence for the last 67 years. That is the most important aspect of this Bill. We are protecting the human interest.

I am so delighted today that our veteran, elder statesmen Advani *ji*, Murli Manohar Joshi *ji* are sitting here this afternoon as we are debating this Constitution Amendment Bill. I am remembering our visionary former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee. It is because, what we are going to do today is to be a solution of an intractable problem, a solution that is going to be found in the spirit of *insaniyat*. Under the sign of *insaniyat*, human beings are taking precedence over territory, small amounts, small pieces of territory that are only going to be notionally exchanged between the two sovereign States of India and Bangladesh.

Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to say that sometimes I hear certain justifications for this Agreement. I can understand that the Ruling Party, in

order to satisfy their recalcitrant constituents in a certain province may often have to make those kinds of arguments. I often hear that this particular piece of legislation and the final settlement of the land boundary between India and Bangladesh will help us resolve the problem of illegal emigration, of smuggling across the borders and so on. That may well be a by-product of the settlement that we are going to reach with Bangladesh. But let us remember that this historic piece of legislation is actually meant for the benefit of the law abiding citizens of India and Bangladesh. Once the entire boundary is demarcated, I would like to see that innocent law abiding citizens of India and Bangladesh should be able to cross the border with dignity. I would urge our External Affairs Minister to have consultations with the Home Minister so that a whole series of integrated check-posts can be set up along the India Bangladesh border. It is because, we want the ordinary people to be able to cross without difficulty. We want music to flow across the border that separates the two Bengals. We want theatre groups from the two Bengals to come to each other and to have their performances. I have spent a lot of time as a student in Bangladesh going about all the districts, working in district record rooms. I have seen how much the people of Bangladesh admire Deshbandhu Chittaranjan Das, Sarat Chandra Bose and Netaji Subhas Chandra Bose. I have seen the best performance of D.L. Roy's Shahjahan play on a stage in Dhaka, not on this side in Kolkata, even though we have great theatre personalities and theatre groups in West Bengal and some of them actually now belong to our Party, the All India Trinamool Congress.

So, I would like to say that let us gift this historic piece of legislation to the people of the two Bengals and also to someone whose birth anniversary, *Ponchishe Boishakh* we are going to celebrate all over the country in two days' time. *Ponchishe Boishakh* is either on the eighth of May or the ninth of May. He not only wrote the National Anthems of our two countries, India and Bangladesh, but all of the songs that he wrote during the Swadeshi Movement of 1905 were inspirational for the *muktijoddha* of Bangladesh in 1971.

"*Bangladesher hriday hote kakhani aponi, tumi ki apurup rupe bahir hole janani, ogo Ma, tomari dekhe dekhe ankhi na fere.*" You know, we cannot turn our eyes from her. We have always envisioned our State Bengal and also Bharat Varsha as the mother. That is the spirit. In those days, we used to recite Jibananda Das's poetry – *Banglar mukh ami dekhiachi, tai prithbir roopomi khunjite jaiarne.* We have seen Bengal's face, that is why we do not need to go out and find beauty in the rest of the world. So, that is what I am being, sort of, reminded of here today.

Finally, I would simply like to say that there is one song. Of course, there were many other songs that were referred to by Ahluwaliaji, Bhupen Hazarika's famous song *Ganga amar Ma, Podda amar Ma.* But let us remember that during the heyday of the Swadeshi Movement, Rabindra Nath Tagore wrote a very beautiful song – *Amra milechi aj mayer dake* - We have actually gathered here at the call of the mother. We are answering the call of the mother in passing this historic legislation in the Lok Sabha today.

On behalf of everyone in this House, it is such a great moment to see that we have risen above all political party differences. We have protected the national interest, the State's interest and the human interest today. So, let us – as has happened in the Rajya Sabha – rise to the full stature of this House and unanimously pass this Constitution Amendment Bill. Let the message go out to the whole of South Asia that we want peace and development for the poor and obscure, who live all across this great Subcontinent.

With these few words, I conclude. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the hon. Minister is going to reply at 5 o'clock. I would, therefore, request the speakers to be very brief in their speeches.

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): It is a very valuable debate, which is going on.

HON. DEPUTY-SPEAKER: It is a valuable debate and I am allowing the Members to participate. It is a Constitutional Amendment and it would go on up to 6 o'clock.

...(Interruptions)

श्रीमती सुष्मा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं साढ़े पांच बजे ही जवाब दूँ। जब सारे सदस्य बोल लेंगे, मैं उसके बाद जवाब दे दूँगी।

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in this historic Constitution Amendment Bill to amend the Constitution of India to give effect to the acquiring of territories by India and transfer of certain territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the Governments of India and Bangladesh.

Sir, I would like to place on record certain factual things so far as the Ministry of External Affairs is concerned. I would like to draw the attention of the hon. Minister of External Affairs that she has been extremely kind in handling various issues, which we often raise. I would just say that in my own case, I have got the reply from the Ministry within a few hours and not within a few days. So, it is time for sincere appreciation for the hon. Minister of External Affairs for handling various issues concerning the Ministry of External Affairs. Our thanks go for that.

Sir, it was well discussed in the House about the very articulation in the opening speech of the hon. Minister, Shrimati Sushma Swaraji. It is a fact and the whole country knows that she is an extremely good articulator. But while articulating what we saw today was that she had very nicely put-forth the sequence of events, which happened in this particular incident culminating into today's event. She has also tried to cover up the stand and the position taken by the BJP in the past and what forced her to come to this position today.

Sir, I would also like to place on record that the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi saw that the Agreement, which was signed between the two Heads of the States need to be respected and honoured. This will definitely send a very positive signal not only to the people of our country but

also the people of world at large. Having said that, it is a fact that the Bill is going to serve a lot in the national interest. While this will result in a modest demographic changes, it will serve a lot of productive purpose for the people who have been affected by this issue. Let us look what would have been happening to fifty odd thousand people who are sitting on the enclaves of Bangladesh and India. They must be keenly watching and they will be the people who will be the beneficiary of today's event. We definitely stand to support the Bill and to implement it in its right spirit.

Having said that, let me come to some of the critical observation which we must be extremely cautious about it. The first issue is the security issue Deputy Speaker Sir. I am a victim in my constituency because of certain illegal immigrations from Bangladesh. This needs to be taken into account. Unless we look at the security issue seriously, we may be a victim tomorrow. So, this is one very important aspect which I would like harp upon and urge the hon. Minister to look into it.

Second, there are many Indians who are living Bangladesh. They will loose their permanent claim to get Indian citizenship. Possibly, they will shed tears today but the Government of India has got its responsibility to see that tomorrow when they become a part of Bangladesh, they may not become victims, or they may not be given a step-motherly attitude. We have got an obligation to do that.

Third, it is important that this piece of legislation cannot be enforced without taking States into confidence.

I am thankful to hon. Minister that she has taken the States into confidence but this need to be ensured that in the implementation process the States are becoming important part and parcel of the entire event.

Another important factor which I would like to urge upon is the very *bona fide* of the Bangladesh people who will take citizenship of India. It is extremely possible that there will be a lot of claimants who are not *bona fide*. So, we have to have checks and balances in the system to ensure that the *bona fide* of the people of Bangladesh so that India does not face problems tomorrow as it is happening today in certain cases.

In the last, we have to prepare a blue print for a time-bound development of all the enclaves which come to our fold. Having said that, while supporting the Bill and while thanking the hon. Minister and the Government, it is important to pass the Bill, it is also equally important that the Bill is implemented in its true letter and spirit so that the people affected get their rightful justice.

श्री विनायक भाऊराव राजत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक को पेश करने वाली विदेश मंत्री सम्माननीय सुआमा स्वराज जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे शिवसेना प्रमुख आदरणीय दिन्दू हृदय सम्राट बाबा साहब जी तकरे हमेशा गर्व से कहते थे कि स्वर्गीय इंदिरा गाँधी जी के बाद इस हिन्दुस्तान की सशक्त महिला नेता अगर किसी को कहा जाए तो उसका नाम है सुआमा स्वराज। उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, उसको सुलझाने का काम, उसे न्याय देने का काम सुआमा स्वराज जी करेंगी। आज यह साबित हो चुका है कि पिछले कई वर्षों से जो पृष्ठ अनिर्णीत था, जो समस्या सुलझी नहीं थी, उस समस्या को सुलझाने का काम इस विधेयक के माध्यम से विदेश मंत्री माननीय सुआमा स्वराज जी कर रही हैं। शिवसेना की तरफ से इस विधेयक को पूरा समर्थन है और भविष्य में भी हिन्दुस्तान की सुरक्षितता के बारे में, रक्षा के बारे में जो-जो निर्णय वह करेंगी, इस सरकार के माध्यम से उन निर्णयों को लेने का काम करेंगी, उसका समर्थन करने का काम शिवसेना पूरी ताकत से करेगी।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से हिन्दुस्तान और बांग्लादेश का जो विवादित प्रदेश था, उसके बारे में तो निर्णय हो जाने वाला है। लेकिन एक पृष्ठ बाकी रहा कि पिछले कई वर्षों से जो बांग्लादेशी और अन्य कई विदेशी नागरिक गैरकानूनी रूप से इस देश में रह रहे हैं, उनके बारे में भी निर्णय लेने का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र के मुम्बई, ठाणे, पुणे या हिन्दुस्तान के कई अन्य प्रदेशों में तासों की संख्या में जो बांग्लादेशी रहते हैं, उनको अभी उनके देश में भेजने का काम भी इस सरकार को करना चाहिए। उनमें से कई लोगों को राशन कार्ड मिला है, कई लोगों का नाम मतदाता सूची में आया है, उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। कई संशोधनों के बावजूद ऐसा साबित हुआ है कि कई प्रांतों में तथा खासकर महाराष्ट्र में जो बालक गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, वे सारे के सारे बांग्लादेश से आ रहे हैं। उनकी मजबूती हो सकती है, उनको वहाँ उनके देश में रोजगार नहीं मिलता होगा, इसके लिए हिन्दुस्तान में आते हैं, वह काम गैर-कानूनी है। लेकिन आज जिस तरीके से सीमा का पृष्ठ सुलझाने का काम हमारी सरकार ने किया है, वैसे ही गैर-कानूनी रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का संशोधन करें और ऐसे गैर-कानूनी रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को अपने देश में भेजने का काम भी इस सरकार को करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि का पृष्ठ सुलझाने का काम तो हुआ है। आदान-प्रदान तो अभी हो जाएगा, लेकिन भूमि की सुरक्षा करने के लिए जैसे पिछले हफ्ते हमारे गृह मंत्री ने बताया कि पूरी जो सीमा है, उसमें सिर्फ 88 परसेंट सीमा की सुरक्षा करने का काम हुआ है। बाकी जो भूमि है, उसके ऊपर जिस तरह की सुरक्षा का प्रबंधन और प्रावधान करना चाहिए, कई कारणों से वह अभी तक नहीं हुआ है। कहीं फॉरेस्ट लैंड है, कहीं अन्यत्र पृष्ठ हैं। मैं यहाँ एक सबमिशन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सुरक्षा के बारे में जब-जब पृष्ठ निर्माण हो जाए, तब-तब फॉरेस्ट की भूमि हो या कोई और भूमि हो, उसके बाजू में रखकर भूमि सुरक्षा करने का प्रावधान होना चाहिए।

एक बात मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भूमि की सुरक्षा हुई लेकिन समुद्र तटीय जो सुरक्षा है, उसके बारे में आज भी गंभीरता से नहीं देखा गया है। मैं सारे सदन को और संबंधित मंत्रालय को बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों पहले जो कसाब मुम्बई में आया, समुद्र मार्ग से आया। वयों आया, कैसे आया, सबको मालूम हो चुका है। एक बार हिन्दुस्तान की सारी की सारी भूमि को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वह भूमि हो या समुद्र तट का क्षेत्र हो, उसकी सुरक्षा के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी परदेशी नागरिक या आतंकवादी हिन्दुस्तान में न आ सके। परदेशी आतंकवादी द्वारा हिन्दुस्तान की सुरक्षा में थोसा पहुँचाने का जो काम हो रहा है, उसके बारे में भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से एक बड़ा कानून बनाने या बड़ा निर्णय लेने का काम माननीय विदेश मंत्री जी ने किया है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir. I am lucky that whenever I stand to speak, you are always there in the Chair. I request you to allow me to speak one or two minutes more because whenever I speak you always restrict me.

HON. DEPUTY SPEAKER: I am also happy to see you. Whenever I preside over here, I have a chance to hear your voice, which is very good.

DR. RAVINDRA BABU : Sir, whenever we talk about Bangladesh, we always get reminded of Bengal Partition, 1906. From Bengal Partition and annulment of Bengal Partition, 1911 the greatest lesson the British learnt was that they could not divide the Bengal people and that they had done a historic blunder. So, they annulled the Bengal Partition and shifted their Capital to Delhi. Afterwards, when Pakistan was portioned, we were tore apart and there came into existence East Pakistan and West Pakistan.

As students of Indian history when we look at the map, it is always inconceivable and very, very surprising to see how Bangladesh can be a part of Pakistan, which is situated on the other side of India. पाकिस्तान उधर है, बंगलादेश इधर है तो ये दोनों एक ही कंट्री कैसे हैं। कोई भी बच्चा मैप को देखेगा तो हैरान हो जायेगा कि ये दोनों एक ही कंट्री में कैसे चल रहे हैं। जैसी अपेक्षा थी, गलत हो गया और दोनों 1971 में विलुप्त अलग हो गये और बंगलादेश बन गया। वह बनना ही था, बन गया। लेकिन But, Sir, we should learn from history. Those who do not learn anything from history, will continue to repeat it. We have to spend a lot of money for protecting our borders with Pakistan and Bangladesh. We have learnt a lesson from Germany. Once it was partitioned into East Germany and West Germany. But they have again united and become a part of European Union.

Sir, as we share the same ethnic culture with Pakistan and Bangladesh, we also share the same ethnic background between Sri Lanka and India. Language spoken in Sri Lanka and Tamil Nadu is same. The British could not do partition of Bengal on the basis of language. Bengal could be partitioned only on the basis of religion. As Tamil Nadu and Sri Lanka speak the same language, I request the hon. Minister to look into the issues between Sri Lanka and Tamil Nadu and facilitate free trade so as to benefit the people of both sides.

Therefore, we, on behalf of Telugu Desam Party, fully support this Bill and congratulate hon. Minister for taking this historical and bold step.

Thank you.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you, Sir, for the opportunity. मैडम, इतिहास में जब भी बंगलादेश का नाम लिया जायेगा, तो इन्दिरा जी का नाम तो हर कोई याद करेगा, लेकिन आज के लैजिस्लेशन के बाद सुआमा जी का नाम भी लोग साथ में याद करेंगे। दोनों ही इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए अमर होकर रह जाएंगे। We sincerely hope that this legislation would bring much anticipated peace and improve relations between India and Bangladesh.

Sir, a lot of data has been shared by my colleagues, but I would also like to reiterate it just for academic purpose. India-Bangladesh Agreement, of course, was done on May 16, 1974. Then, a protocol was signed on September 6, 2011. When we speak about 2011, we will have to remember former hon. Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, who had taken an initiative combined with the Bangladesh Government. They had conducted the headcount, which was long pending for 40 years. After the headcount was conducted, it became easy for us to bring this legislation. Through this legislation, today we are talking about 111 Indian enclaves in Bangladesh, which is an area of 17,160 acre. There are 51 Bangladesh enclaves in India which comprise of 7,110 acre of area. There is an exchange of land on paper but physical कंट्रोल तो अपने-अपने देश में हैं। The headcount conducted in July says that 51,549 people in India and 14,215 people in Bangladesh will be affected by this legislation. इनकी जिंदगी में एक अच्छा चेंज आएगा और हम आशा करते हैं कि इतने दिनों तक इस सब के ऊपर जो ह्यूमैनिटेरिन वायलेंस हो रहे थे, ह्यूमन राइट्स के वायलेंस हो रहे थे, ये सब भी आज से खत्म हो जाएंगे।

India will receive adverse possession land comprising of 2,777 acre and will transfer 2,267 acre of land to Bangladesh as well. Through this Bill we will be amending our First Schedule of the Constitution and will be amending the territories of Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura.

माननीय मंत्री जी ने शुरू में ही सारे मेम्बर्स के स्पीच को 'नल एण्ड वॉयस' कर दिया, क्योंकि सभी यह कहना चाह रहे थे कि बी.जे.पी. ने पहले इसका विरोध किया था, बी.जे.पी. असम को इससे बाहर रखना चाह रही थी, लेकिन आपने इसके बारे में सारा कुछ बोल कर हमारे स्पीच को ही खत्म कर दिया। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बोलने को बचा नहीं है। लेकिन, यह संयोग की बात है और वक्त का तफाजा है कि जिस बी.जे.पी. ने पहले इसका विरोध किया था, अब उसी बी.जे.पी. की सरकार को इसे लेकर आना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का राज्य सभा में सपोर्ट किया है, वैसे ही इस हाउस में भी वह इस बिल को पारित कराने में सहयोग करेगी। इस बिल के पास होने के बाद डेफिनेटली, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि बाइलेटल को-ऑपरेशन होगा, सिक्वैरिटी, ट्रेड्स, सब में सुधार होगा।

हमारी पार्टी की तरफ से एक-दो सुझाव हैं, जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ। हमारे तेलंगाना के लोगों का दुर्बई, सऊदी अरब आदि देशों में माइग्रेशन का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। पर, जब से आदरणीय सुआमा जी विदेश मंत्री बनी हैं, we could get back almost 74 bodies, which is the highest in count, highest in number. पिछली किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। माननीय मंत्री जी इतनी एक्टिव हैं। जब इस बिल के माध्यम से लैंड ट्रांसफर हो जाएगा, और दोनों देशों के बीच में इतने सारे लोगों का एक्सचेंज होगा, तो मैं माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आप इन सभी पांच राज्य सरकारों को विश्वास में लीजिए। I would request that the Centre has to kindly oversee the developmental plans, नहीं तो एक-दो महीने के बाद जब इनिशिएल यूएफोरिया खत्म हो जाता है तो फिर वहां के लोगों के विकास के बारे में कोई नहीं सोचता है। As an External Affairs Minister, since you have culminated this issue to its logical end, kindly look into the development aspect of these people also.

जहां तक फेंसिंग की बात है, तो बॉर्डर स्टेट्स के बहुत सारे मेम्बर्स यहां इस फेंसिंग के इश्यू को उठाते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी पूरी बाउंड्रीज, जो तकरीबन चार हजार किलो मीटर के आस-पास है, उसकी भी पूरी फेंसिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ, हमें भारत के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, इतना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से एक और गुजारिश करना चाहूंगी। भारत-बांग्लादेश के बीच के लैंड बॉर्डर्स की तो हमने बात कर ली, पर भारत-बांग्लादेश के बीच में और भी कई इश्यूज हैं। जैसे दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम इश्यूज हैं। Bangladesh also claims the same waters and we also claim the same waters. This issue needs to be addressed.

Between India and Bangladesh, we share 54 rivers, not one or two. We also have a Joint River Commission and a Joint Economic Commission. लेकिन, इनका जो रोल है और जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं या हिन्दुस्तान के सीमावर्ती राज्यों में रह रहे हैं, we are not able to give confidence to these people. Sir, through you, I request the hon. Minister - regard to sharing the water of the River Ganga, River Teesta and other rivers - to take a pro-active role and conclude and settle these matters for once and all.

Madam, we have nine major neighbours, like Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka. इन सारे देशों के साथ हमारी जो विदेश नीति है, मुझे लगता है कि कहीं-कहीं यह थोड़ी प्रॉब्लम में है। आपको भी मालूम है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में हमारा रोल बहुत ज्यादा था। लेकिन, आज एक ऐसा माहौल बन गया है कि बांग्लादेश चीन के साथ एलाइन होना चाहता है। आज बांग्लादेश चीन के साथ अपने व्यावसायिक संबंध बढ़ा रहा है।

Similarly, look at the issue of Sri Lanka also. They have been very close to us. Of course, there were problems in-between which we have sorted out. पर, अब चीनी सबमैरिन्स श्रीलंका के यहां रुकते हैं, और श्रीलंका भारत को बताते भी नहीं हैं। I just want to say that we are a very huge country neighbouring with very small countries. अगर हम एक बार उनके सामने जाकर देखेंगे तो उन्हें ऑब्बियेक्स्टी एक डर लगेगा कि इतना बड़ा एक पड़ोसी देश हमारे पास है। But it is also our responsibility as a big brother that we play a good role and we share and settle the issues between these countries. For example, our Tamil brothers continuously keep raising the issues of Kachchatheevu Island and fishermen. उस पक्ष से भी हमेशा 'राम सेतु' की बात उठाई जाती है। हमने सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत पढ़ा है। जब भी हमारे पार्लियामेंट में 'राम सेतु' की बात उठती है तो श्रीलंका के लोग अन-कॉम्फर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके वेसल्स को जाने में दिक्कत होती है। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जो

हमारे पार्लियामेंट में हमें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वह दूसरे देशों के लोगों के मन में ऐंग्ज़ाइटी पैदा करती है।

Sir, hon. Minister of External Affairs is a very knowledgeable person. She has a historic role to play in this Government. I would request her to let our foreign policy not be dictated by China or Pakistan. Of course, we have problems with Pakistan and we have problems with China, but I believe that independently, we should deal each country as a separate entity.

Sir, we should also look into another very important matter. Today, since China has excess money, it is investing everywhere. China has invested in Sri Lanka Ports, and China is investing in Bangladesh. This will be a problem in the future. So, we will really have to look into it.

Personally, do not think that I am opposing the Government's position on certain issues, but instead of getting a Bullet Train and spending Rs. 60,000 crore on a Bullet Train, why do not we invest in our neighbouring countries. We need to give more money to Nepal, and we need to invest more money in Afghanistan. We cannot have an unstable Afghanistan, and we cannot have an unstable Pakistan. Let us work more towards improving our relations with the neighbouring nations, and let our foreign policy not be dictated by China and Pakistan. Thank you so much.

श्री मोहम्मद सतीम (रायगंज) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक है। हमारी विदेश मंत्री सुआमा जी ने इसे यहाँ लाकर पहले ही सेन्चुरी मार दी है। यह 119वाँ संशोधन है, लेकिन जब यह पास करेंगे तो यह कोई को-इन्सीडेंस नहीं है कि यह हैड्लैथ होगा, तो आपकी सेन्चुरी के लिए भी आपको बधाई हो।

वर्ष 1974 में इन्दिरा गाँधी और मुजिबुर्रहमान की इंदिरा-मुजीब चुक्ती एग्रीमेंट हुई थी। हमें 41 साल लग गए इस देश में संसद में इस मामले को लाने और इसे निबटने में, जबकि वर्ष 1974 में ही बांग्लादेश उस एग्रीमेंट को रिविटफाई कर चुका था। हमारे कानून के तहत, हमारे संविधान के तहत हमें संविधान में संशोधन लाना था। मैं चूँकि खुद विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, पहले ही यह कह देना चाहिए, अवसर स्टैंडिंग कमेटी में किसी मामले को भेजने में सरकार यह कहती है कि समय जाया होता है। हाई मंडीने में स्टैंडिंग कमेटी ने यूनिनिमसली रिपोर्ट पेश कर दी। फिर भी सरकार को चार महीने से ज्यादा का समय लग गया, सवा चार महीने लग गए, अपना मन बनाने और कुछ लोगों को मनाने में, देर है, पर दुरुस्त है। विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री के नेतृत्व में पहलकदमी की है, जिसका यह नतीजा है। परना कल तक यह बात चल रही थी कि होना है या नहीं होना है, कहाँ तक होना है, ट्रैकेटेड होगा या पूरा होगा, इसके लिए भी आपको बधाई है।

सबसे अच्छा होता कि यह उस दौर में जब मिसेज इन्दिरा गाँधी प्राइम मिनिस्टर थीं और उधर मुजिबुर्रहमान देश को आजाद कराने के बाद बंगबन्धु का पूरी दुनिया में एक कद था, उस वक्त इसे लागू कर सकते थे। सरकार किस तरह से काम करती है, यह इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं है, मामला यह है कि उस वक्त यह नहीं हुआ। चूँकि उसके लिए स्टेट्समैनशिप चाहिए और हिम्मत चाहिए। हमेशा कुछ लोग होते हैं, आज भी हैं, सरहद के उस पार भी हैं, सरहद के इस पार भी हैं, जो इन तमाम सवालों को तर्क के साथ, तथ्य के साथ या मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखकर राजनीतिक, धर्म या अल्ट्रा-नेशनलिज्म की तरह देखते हैं। इस तरह से डिस्प्यूट को सॉल्व करने के बजाए पाला जाता है। उस कंट्रोवर्सी की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। भारत बांग्लादेश के बीच उतने ज्यादा डिस्प्यूट नहीं हैं। लैंड बाउंड्री के डिस्प्यूट इस बिल से कम से कम परमानेंटली सेटल होंगे। इससे जो रिस्कमिज होती है, चाहे वह रैब हो चाहे हमारे यहां बीएसएफ हो, कभी-कभार सीमा पर जो होता है, वह भी बंद होगा। जो सिक्कोरिटी का वक्शन है, स्मगलिंग का सवाल है या जो देश की विरोधी ताकतें हैं, जो हंगामा करना चाहती हैं, ऐसी शक्तियाँ जो सीमा पर ऐसा माहौल पैदा करती हैं या ऐसे माहौल का फायदा उठाना चाहती हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा, लेकिन यह आज का विआय नहीं है।

मैं इस वक्त ज्योति बसु, बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर की बात को याद करूँगा। इसी छिटमहल का मामला, एन्वलेव का मामला, बेरूबासी यूनिशन जो दो टुकड़े हो गई, कुछ हमारे हिस्से में है, कुछ उनके हिस्से में है, बीच में तीन बीघा का कोरीडोर का मामला था, इसी प्रोटोकाल के तहत, लैंड-बार्डर एग्रीमेंट के तहत वर्ष 1992 के जून महीने में एक खत एक्सचेंज करके भारत-बांग्लादेश में उस मामले को हल कर लिया गया। उस वक्त वाम मोर्चे के अन्दर भी बहुत-से सवाल थे। यह बात वर्ष 1950 से चल रही है। यह सब बातें आ गयी हैं, मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 'नेहरू नून एग्रीमेंट' हो या सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस हो। रेडवलीफ साहब जो किए थे, अभी प्रो. युगत बोस ने एक अच्छे हिस्टोरियन की तरह अपनी बात को रखा है। उनका मिशन बहुत हड़बड़ी में हुआ है। पूरा देश पार्टीशन के लिए तैयार था, लेकिन बंगाल पार्टीशन के लिए तैयार नहीं था। अगर उस वक्त कांग्रेस नेतृत्व 'नेहरू लियार्कट एग्रीमेंट' मान लेती, या सी.आर.दास, सरद बोस, ए.के. फज़लुल हक की रहुमुर्दाई को स्वीकार कर लेते तो हमें आज यह टुकड़ा देखने को नहीं मिलता। यह इतिहास है। नेतृत्व को दूरदर्शी होना पड़ता है। एक घर के तीन टुकड़े हो गये, हम फिर से मिलान की बात नहीं करते हैं। बांग्लादेश आजाद रहे, पाकिस्तान अपनी जगह पर रहे, हम अपनी जगह पर रहें, चूँकि हमारे देश का साइज ऐसा है, हम जब भी यह कहते हैं कि चलो एक हो जाएं तो बांग्लादेश के अंदर पेशानी हो जाती है। भारत विरोधी तत्व कहते हैं कि भारत हमें ले लेना चाहता है। हम अच्छे संबंध चाहते हैं। हम अच्छे संपर्क चाहते हैं। हमारे अंदर जो एक्सचेंज है, चाहे वह कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, रैड, कॉमर्स या लिज़ारत हो, वे और अच्छे होने चाहिए। We have paid the cost of conflict; now, we have to reap the harvest of cooperation. यह ज्यादा जरूरी है, हमारे पड़ोसी देश के साथ संपर्क करने के लिए। आपकी भाषा में सी.बी.एम. होता है - काफिडेन्स बिल्डिंग मेजरर्स, जैसे हम ने गंगा के पानी का मुआयना किया था, उसी तरह कविता जी ने कहा है कि ऐसे कई इश्यूज हैं, 'to look forward and beyond'. यह हमारा लोकल बॉर्डर ट्रेड हो, जो रेडिशनली होते थे, रेडवलीफ साहब ने लकीर खींच दिया, सियासी माहौल ऐसा बन गया, दंगा-फसाद का माहौल हो गया, हम दो टुकड़ों में बंट गये, लेकिन गांव तो एक ही है, लोग तो एक ही हैं। वहां कैटल्स की स्मगलिंग की जाती है। आतंकी इस पार से उस पार हो जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों को जो जरूरत है, उनको हम शेयर नहीं कर सकते हैं। सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से लोकल बॉर्डर ट्रेड को, जो लोकल हार्ट की बात है, बांग्लादेश से भी प्रोजेक्ट था, उसको आप आगे बढ़ायें।

मैं खुद उतर दिनाजपुर सीमा-क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। त्रिपुरा से लेकर पूरे नॉर्थ-ईस्ट का बॉर्डर ट्रेड बढ़ना चाहिए। इसी तरह हमारा जो ट्रांजिट की फैसिलिटी है, बांग्लादेश को फायदा हो, हमें भी फायदा हो, नॉर्थ-ईस्ट के साथ हमारा जो मूल भूखंड है, उसका सिर्फ इंटीग्रेशन, यह सिर्फ कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी का मामला नहीं है। नॉर्थ-बंगाल और नॉर्थ-ईस्ट के साथ, चाहे बांग्लादेश के विद्वानों के साथ साबरूम हो कर, त्रिपुरा को सी-एक्सेस मिले या बांग्लादेश के पोर्ट को नेपाल के साथ ट्रेड करने के लिए हमारे नॉर्थ बंगाल के अंदर से कॉरिडोर मिले। पूरे विश्व में इस तरह से रिजनल कोऑपरेशंस हो रहे हैं तो हमें भी यह पूरे एशिया में दिखाना पड़ेगा। मैं इस बात को इसलिए खींच रहा हूँ कि इस वक्त एशिया में कई मुल्क के अंदर बमबासी हो रहे हैं, लोग अपने मामले को हल नहीं कर पा रहे हैं, गोलीबाजी हत्या और खून-खराबा हो रहा है। ऐसे समय में हम दो देशों के बीच में एग्रीमेंट कर रहे हैं और यह संसद इसको पास कर रही है, यह पूरे विश्व के सामने एक नमूना है। हम पंचशील की बात करते थे, हम शांति की बात करते थे, सदियों से हम जिस बात को कहते आये हैं, दक्षिण एशिया जो पूरे विश्व को दे सकती है, बुद्ध, जैन के जमाने से, आज हम उस मिशाल को पूरे विश्व के सामने रख सकते हैं कि मामला गोली से नहीं बोली से हल हो सकता है और इसका यह नमूना है।

दूसरी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है कि जब पहले यह सवाल आया, मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आर्किव करना चाहता हूँ, चूँकि उस वक्त हमारे देश में ऐसा हो गया, उसके लिए हमें अफ़सोस है, वर्ष 1974 से बांग्लादेश मतलब - इलीगल माइग्रेंट। बांग्लादेशी इलीगल, यह फेज बन गया है, यह पवाइन हो गया है कि बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर घुसपैट

कर लेना चाहते हैं। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हिन्दुस्तान का मतलब है कि वह हमें ले लेगा। उसने पाकिस्तान को हरा कर बांग्लादेश को आजाद किया है तो हो सकता है कि वह यहां कब्जा कर ले, हमारे ट्रेड और कॉमर्स को ले ले। इससे भय, जेनोफोबिया का वातावरण तैयार होता है। वह हम ने माननीय सदस्यों के अंदर भी देखा है। बाद में हमारे चेयरमैन और श्रीमती सुजाता सिंह दी देन फॉरेन सेक्ट्रेट्री थी, मैं उनकी बात भी करूंगा कि she led from the front and she convinced us. उन्होंने जो प्रजेंटेशन दिए उससे लोगों के मन में जो भय था उसे दूर किया गया और कमेटी की प्रक्रिया में ऐसा होता है। स्टैंडिंग कमेटी में कन्सेन्स बिल्ड-अप करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल की रूटिंग पार्टी है, सुगत बोस ने कमेटी में कहा है कि उसके बाद क्या होगा? चूंकि एक डर या भय रहता है, जिम्मेदारी रहती है। आबादी का मामला हो, पुनर्वास का मामला हो। कमेटी में हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया और समस्या सुलझाने की कोशिश की कि हम लोग यह जिम्मेदारी ले रहे हैं। लोग ह्यूमन प्रोब्लम को जमीन की समस्या समझ सकते हैं, लोग इसे देश की समस्या समझ सकते हैं।

जब हम कूच बिहार में इनवलेव के लोगों से बात करते हैं, जो एडवांस पोजिशन में हैं, उसे डिज्यू करना है, डिफैक्टो करना है। लेकिन इनवलेव में खेती का सवाल, खेती का सवाल, दवाई का सवाल, अस्पताल का सवाल, थाने का सवाल और शिक्षा का सवाल इन सबसे उनको बहुत परेशानी होती है। जहां वे रहते हैं वह उनका देश नहीं, जहां वे जाते हैं तो कहा जाता है, तुम कहां से आए हो। बच्चों को स्कूलों में भर्ती करने के लिए लोकल गार्जियन का नाम पिता के रूप में लिखाना पड़ता है नहीं तो वे कहेंगे कि तुम दूसरे देश से आए हो, इस समस्या से उनको मुक्ति मिलेगी। यह केवल शुरूआत है, अंत नहीं। जब इनवलेव का मामला हल हो जाएगा, एडवांस पोजिशन का मामला हल हो जाएगा, जैसे कविता जी ने कहा चाहे वह तीस्ता जल की बात हो या बाकी नदियों की बात हो, चाहे ट्रांजिट की बात हो, चाहे एनर्जी का मामला हो, चाहे सिवियुटिटी का मामला हो। आज के दिन बांग्लादेश की हकूमत हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित एक सकारात्मक रवैया अपना रही है। हम भी अपने देश के किसी हिस्से से बांग्लादेश के खिलाफ काम करने की इजाजत नहीं दे सकते, हमारे देश के खिलाफ भी बांग्लादेश को काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। नार्थ-ईस्ट की बहुत सारी समस्याएं सिवियुटिटी एंगल से बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने रास्ता दिखाया कि किस तरह से जब देश का मामला या मानवीय सवाल आता है, तब सदन के अंदर और सदन के बाहर कैसे जुड़ाव पैदा होता है। इससे सीखा लेकर बाकी विभाग भी काम कर सकते हैं कि किस तरह स्टैंडिंग कमेटी का इस्तेमाल करके विधेयक को एक साथ मिलाकर आम सहमति से तैयार की जा सकती है। अगर हम विदेश के साथ जमीन का मामला हल करने के लिए समझौता करने के लिए एक राय हो सकते हैं तो क्या देश के अंदरूनी मामले में एक नहीं हो सकते? ... (व्यवधान) It will be interesting. Allow me to speak for one minute. This is a quotation in Bengali. महान आनंदा शंकर रॉय ने देश के विभाजन के बाद लिखा:

Teler Shishi Bhanglo Bole

Khukur Pare Raag Karo

Tomra Je Shab Buro Khoka

Bharot Bhenge Bhag Karo

Taar Bela ?

देश का बंटवारा एक हकीकत है, हम वहां से वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम अच्छे पड़ोसी की तरह दूसरे देशों के साथ जी सकते हैं। यह संदेश हम दूसरे मुल्क को दे सकते हैं। जब बच्चा शीशी तोड़ देता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और जब बड़े बच्चे मुल्क को तोड़ रहे हैं तब कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है? हम तोड़ने की बजाए जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पर हम सब एक राय हैं, यह बहुत ही गौरव की बात है।

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, I thank the Chair for giving me this opportunity. Let me also, on behalf of my Party, the YSR Party, congratulate the hon. Minister for bringing this historic legislation. Particularly for the last ten months where there is no harmonious and friendly discussion on most of the Bill, this Bill has given us an adequate opportunity for exchange of so many pleasantries. I could see that today in the newspapers. This morning, she was kind enough to mention that we should give due credit to the former Prime Minister of India who has made this atmosphere very friendly. I hope this will continue further.

This piece of legislation will make the 1974 India-Bangladesh Land Boundary Agreement operational, and it allows swapping of land. Bangladesh gets 260 acres and India gets 174. The figures vary and, therefore, the hon. Minister may clarify what exactly is the extent of land India and Bangladesh get.

This piece of legislation will lead to very a friendly bilateral relationship between India and Bangladesh. If the hon. Minister of External Affairs could solve the other major issue of Teesta waters dispute, we will have a very friendly relationship with our most friendly neighbour Bangladesh.

I read in some newspapers that as much as 10,000 acres of enclaves are going to Bangladesh and it is going to shrink the boundaries. Hon. Minister may clarify these points at the time of replying to the debate. I believe it changes the contours of the boundary. We would have appreciated this point much better if a small map had been distributed to the Members.

Now the issue is that the Statehood of as many as 54,000 has to be settled by way of this piece of legislation. As many as 34,000 people are likely to come to India and the balance to Bangladesh. It is very unfortunate that for the last 41 years not even basic amenities with regard to education, health and transport, and law and order have been provided to these people. Thank God, the hon. Minister has taken up this onerous responsibility to ensure that basic amenities are made available to these people. That may be taken up very quickly.

With regard to the citizenship, I am of the opinion that option may be given to the people. Whoever wants to go to Bangladesh may be given Bangladeshi citizenship and vice versa. We thank the hon. Minister particularly for including Assam also which made this 100 per cent operational. We also request that whatever rehabilitation package has been promised to these people should be implemented soon so that basic amenities are provided to these people.

Thank you.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to reiterate that our hon. External Affairs Minister, Madam Sushma Swaraj, has got a heart of gold and she has proved it once again. The very thought is commendable and very much appreciated by all of us.

16.58 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

The Constitution (Hundred and Nineteenth) Amendment Bill which will allow the operationalisation of 1974 India-Bangladesh Land Boundary Agreement, I would like to reiterate here, is against the interests of the country as it will badly affect the bordering States of Assam, Meghalaya, West Bengal and Tripura. I feel personally and our party All India United Democratic Front's stand is that there are other ways of building relationship with neighbours. Giving away land, land of States like Assam where we lose lakhs of hectares every year to erosion and flood, is not the only way of having good friendly relationship with neighbours, and this will not solve the boundary problem.

We feel the boundary problem should be permanently solved by erecting a concrete wall between India and Bangladesh as this will permanently solve the everlasting scourge of 'Bangladeshi' which has been tagged to all the minorities. We believe that there should be a permanent solution by erecting boundary wall. But giving so many acres of land from India I do not think is the solution to having good relationship with your neighbour.

17.00 hrs.

The NDA Government has been given the final nod in the Rajya Sabha and this will become operational. But the NDA had opposed this when the UPA Government tried to do the same thing.

Madam, Assam is a State where every year we have flood and erosion. Normal citizens of India are tagged Bangladeshis. Here, I would just like to mention how these people, who are innocent citizens of India, came to be labelled as Bangladeshis. Suddenly, overnight there is a gush of flood in their houses and they have to save the lives of their children. In such a situation, they have no time to save their documents. Eventually, they lose their precious documents in flood. As a result, they lose hundreds of acres of land. These very people do not get the documents eventually and are labelled as Bangladeshis. But construction of a concrete wall between India and Bangladesh and a boundary demarcation will be a permanent solution and this scourge of 'Bangladeshi' will go away from minorities of Asom. I would also like to say that people living in the periphery of boundary between India and Bangladesh are suffering a lot. Their suffering should be permanently solved by demarcating the land permanently between the two nations.

On behalf of the people of Assam, I would request hon. Prime Minister to fulfil his election promise that not even an inch of land will be given to Bangladesh. This was promised by our hon. Prime Minister and I would request the Minister of External Affairs to kindly withdraw the Bill for the larger interest of the country and its people, especially the people of Asom.

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Madam, I stand here to argue on the Constitution (One Hundred and Nineteenth Amendment) Bill 2013 on land transfer between India and Bangladesh. Though we never wanted partition, it was imposed upon us and lakhs and lakhs of people were displaced and killed. This is the scourge of history we are facing. Bangladesh was born from our home and having taken birth, the burden of Bangladeshis is being faced by Asom. Asom has carried this burden for a long time particularly after the war of 1971 and liberation of Bangladesh. The people who came as illegal infiltrators settled in Asom. All the promises made by different Governments in the past either by the Congress Government or AGP Government failed to bear any result.

The demarcated line by Radcliffe was drawn haphazardly and it has not solved the border problem. Many enclaves were left undecided and un-demarcated, where our people reside in their land and their people reside in our land. At the initial stage, we opposed this land transfer. Asom was against this transfer of 268.39 acres of land. Originally, it was 499 acres but it was settled at 268.39 acres. Keeping the matter alive, the Bangladeshis did infiltrate India through that corridor and also smuggled cows and cattle to the extent of 15 lakhs cattle to Bangladesh. The ping food industry was set up in Bangladesh border and it has grown in Bangladesh through smuggling of cows from India. The riverine area is unprotected. The borders are porous. The BSF is not able to manage the border. The total length of the border is 4096 kilometres. The agreement was signed on 16th of May, 1974. It will complete exactly 41 years after 8 days.

That has not settled it. Again, in 1992, some settlements were made. Ultimately, in 2011, Dr. Manmohan Singh and our Chief Minister Shri Tarun Gogoi went to Bangladesh and signed a protocol. That protocol is being ratified now. We opposed it. The indigenous organisations of Assam opposed the transfer of land to Bangladesh so far as Assam's land is concerned. We had a strong opposition. We fought. We agitated. The Bharatiya Janata Party was a part of that agitation. ...(*Interruptions*) But ultimately it came to the interests of the nation. The Congress Government in the State took a U-turn and dashed a letter to the Prime Minister of India opposing the exclusion of Assam from the land transfer. ...(*Interruptions*) Ultimately, we agreed to it. ...(*Interruptions*) That letter is on record.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): You show the record. ...(*Interruptions*)

SHRI RAM PRASAD SARMAH: When the hon. Minister of External Affairs speaks, she will reply. Please keep quiet. Please sit down. ...(*Interruptions*)

This is the Chief Minister's letter. Hon. Minister will reply. ...(*Interruptions*) So, we had to include Assam in the land border agreement. We had opposed this because we wanted total protection for Assam against infiltration. The identity of the Assamese people must be protected. The Congress Government failed to protect the identity of the Assamese people, the indigenous people of Assam. The Congress people wanted to make Assam a second Bangladesh. We opposed that tooth and nail in Assam and in Parliament. I must proudly say that even today, we are opposing it on behalf of the people of Assam. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are going to speak.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will take care; do not worry.

...(Interruptions)

SHRI RAM PRASAD SARMAH : The area in occupation of Bangladesh is huge. There is nothing done by the past governments to detect and deport the Bangladeshis. ...(Interruptions)

We also want the minorities in Bangladesh who came to India as refugees, the Hindu Bengalis, the Chakmas, the Hajongs, and the Christian minorities to be protected. That is our demand. ...(Interruptions) We will have to see that the Hindu minorities and Chakmas and Christians and others are not leaving Bangladesh. The Government of India must ensure that while giving the land. ...(Interruptions) Two hundred and sixty-eight acres is a big chunk of land. We must ensure that minority religions of Bangladesh are protected thoroughly. In some sense, we are parting away with 268 acres of land. ...(Interruptions) It will initiate a new process and a new chapter in the relations between the two countries. It will also open a transit route to Agartala, Mizoram and Barak Valley in Assam.

With these words, I support the Bill and congratulate the Foreign Minister for initiating the move. But at the same time I strongly deprecate the methods and procedures adopted by the Congress-ruled State of Assam.

Thank you.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam Speaker, in this kind of a Bill where we are not very conversant with foreign affairs, they should have given a map with the Bill so that we can understand. ...(Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM: Or, we can use the screens.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री सुश्री सुभाषिणी स्वराज जी जो आज 119वाँ सैद्धांतिक संशोधन विधेयक लेकर आई हैं, यह स्वागत योग्य है। मैं उनको बधाई देता हूँ।

वर्ष 1971 में बंगलादेश का जन्म हुआ। बंगलादेश का गठन होने के बाद वर्ष 1974 में भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच इंदिरा गांधी और रहमान जी के नेतृत्व में सीमांकन के संबंध में जो करार हुआ था, उसके बाद डा. मनमोहन सिंह जी का वर्ष 2013 में भी इस दिशा में प्रयास रहा लेकिन उसे सही मायने में अमलीजामा पहनाने का काम आज हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, पड़ोसी बंगलादेश का रिश्ता एक मित्र देश के रूप में रहा है और आगे भी रहे, इसी के लिए यह बिल लाया गया है। बंगलादेश को बनाने में हमें काफी बलिदान देना पड़ा था। इस बिल में जो थोड़ी-बहुत परिवर्तन थी, माननीय मंत्री जी ने सीमा से लगने वाली राज्य सरकारों से बातचीत करके उसका समाधान करने का प्रयास किया है। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है, मैं एक बात जरूर जानना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि भारत के जो लोग बंगलादेश पहुंच गए हैं और बंगलादेश के लोग हिंदुस्तान में हैं, वे लोग वापिस अपने-अपने देश में आ सकें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्ष 1978 में बहुत बड़ी संख्या में बंगलादेश के लोग हिंदुस्तान की सीमा में आ गए और वापिस नहीं गए। इस बिल के माध्यम से जो सीमांकन करार हो रहा है, वया जो टापू हिंदुस्तान की सीमा में आएं और वहां जो बंगलादेश के लोग रह रहे हैं वया वे वापिस बंगलादेश जाएं, इसे माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर बताएं।

श्री गौरव गोमोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदया, आज मैं 193 कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह ऐतिहासिक अमेंडमेंट है और आज एक ऐतिहासिक दिन भी है जब भारत और बंगलादेश के बीच में जो दोस्ती है, वह और ज्यादा गहरी होने वाली है। मैं इस बारे में ज्यादा राजनीतिक तर्क नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आज एक बहुत सुनहरा और ऐतिहासिक दिन है। भारत और बंगलादेश की जो दोस्ती है, वह आज से नहीं बल्कि वर्ष 1971 से है जब बंगलादेश की लिबरेशन वॉर हुई। इस वक्त हमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद आती है क्योंकि उस समय इंदिरा जी की सरकार ने पाकिस्तान की आर्मी को हराकर बंगलादेश की आवाज को आजादी दी। इस वजह से आज बंगलादेश की आवाज और भारत की जनता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सम्मान करती है। वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी जी और मुजिबुर्रहमान के बीच में ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। वर्ष 2011 में इस दोस्ती के बीच में एक विशेष समय आया जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह शेरख हसीना जी के साथ एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल ले कर आए। मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मंत्री जी को भी पता होगा कि इस बिल के साथ जितना ज्ञान हमें बांटना चाहिए था, वह नहीं बांट पाए। अभी भी संसद में बहुत लोग चाहते हैं कि इस बिल के बारे में वे और ज्यादा बारीकी से समझ पाएं क्योंकि कहीं न कहीं आज इस बिल को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, प्रोपेगेंडा से निकलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे जाकर विस्तार से इस बारे में एक डायलॉग निकालें जो सभी सांसदों को समझा पाए कि यह बिल क्यों भारत के हित में है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस बिल को क्यों ले कर आए। लोगों को पता लगना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने इसका समर्थन क्यों किया था।

इस बिल में तीन मूल चीजें हैं। एक चीज एनवलेव है। एनवलेव वह चीज है जो भारत की मिट्टी या बंगलादेश की मिट्टी है, एक देश की मिट्टी दूसरे देश की सीमाओं में बहुत अंदर तक समा चुकी है कि वहां प्रशासन की किसी प्रकार की भी सुविधा लोगों को नहीं दे पाते हैं। इंडिया के अंदर बंगलादेश के ऐसे 51 एनवलेव हैं और बंगलादेश के अंदर इंडिया के 111 एनवलेव हैं। अगर आप भूमि का आकलन देखें तो भारत के जो 111 एनवलेव हैं, उनकी कुल भूमि 17170 एकड़ है और बंगलादेश के जो 51 एनवलेव हैं, उनका आंकड़ा 7100 एकड़ है। यहाँ हमारे यूडीएफ के साथी ने कहा कि इसमें हम भारत की मिट्टी बंगलादेश को दे रहे हैं, यह गलत है क्योंकि वे सिर्फ एनवलेव की बात कह रहे हैं। एनवलेव के अलावा एक चीज एडवर्स पोजेशन है। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र है, जिस पर बंगलादेश का कब्जा है। कब्जे का मतलब यह है कि वहाँ दूसरे देश के प्रशासन का कंट्रोल है। जैसे ही एडवर्स पोजेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बंगलादेश में कोई ऐसा क्षेत्र है जो कानूनी तौर पर बंगलादेश का है लेकिन इंडिया का वहाँ प्रशासनिक कंट्रोल है। यदि एरिया देखें कि किसके पास कितना एरिया आता है, तो इंडिया के पास 2,777 एकड़ भूमि और बंगलादेश के पास 2738 एकड़ भूमि है। जहाँ बंगलादेश 2,738 एकड़ भारतीय भूमि पर एडवर्स पोजेशन कर चुका है। उससे हम आज 470 एकड़ भूमि भारत लेकर आए हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि ... (व्यवधान) रेडविलफ ने जो बाउंड्री बनायी ... (व्यवधान) मैडम स्पीकर, कुछ लोगों को तथ्य पसंद नहीं हैं, वे राजनीतिक लाभ के लिए नहीं चाहते कि सत्य बाहर आए। ... (व्यवधान) आपके प्रधानमंत्री जी खुद इसका समर्थन कर रहे हैं, शायद उन्होंने कुछ सोचकर इसका समर्थन किया होगा। ... (व्यवधान) सूटबूट की सरकार ने इस बिल में सूझबूझ लगायी है, ... (व्यवधान) सोच-समझ से यह बिल आगे बढ़ा है। जो ऐतिहासिक भूल की गयी थी, रेडविलफ ने ऐसा बाउंड्री बनाया था कि बंगलादेश के पास 2738 एकड़ भूमि उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के एडवर्स पोजेशन में था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बिल से उस ईस्ट पाकिस्तान से हम लैंड वापस लेकर आए हैं और इंडिया को 470 एकड़ भूमि मिली है। ... (व्यवधान) इसे हम लेकर आये हैं, हमने यहाँ एनवलेव की बात की, एडवर्स पोजेशन की बात की।

तीसरी बात अन-डिमाकैटेड बाउंड्री के संबंध में है। छः किलोमीटर तक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहाँ पर हमने सीमा बनायी ही नहीं। यह त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम में है। उस छः किलोमीटर पर हमने कभी सीमा नहीं बनायी, इसलिए अभी तक इसके बारे में पता नहीं है कि वहाँ पर की वह मिट्टी बंगलादेश की है या भारत की मिट्टी है। आज इस प्रोटोकॉल और इस ऐतिहासिक बिल के द्वारा हमने उस छः किलोमीटर पर अपनी सीमा बनायी है। इससे क्या लाभ होगा? इससे यह लाभ होगा कि जो हमारी मिट्टी है, वह हमारे पास वापस आ गयी है। और इससे मंत्री जी भी सहमत होंगी कि एडवर्स पोजेशन के क्षेत्र में असम को स्पेशल केस के हिसाब से देखा गया है। एडवर्स पोजेशन में क्या होता है, इस बिल में हमने यह सिद्धांत निकाला है कि वतो यह भारत की मिट्टी है, लेकिन चूंकि इस पर बहुत समय से बंगलादेश का प्रशासनिक कंट्रोल रहा है, उसे हम बंगलादेश को दे देते हैं और बंगलादेश की मिट्टी जो भारत में है, यह लीगली बंगलादेश है, लेकिन बहुत समय से वहाँ पर भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसे हम भारत में ले लेते हैं। लेकिन इस बिल में असम के केस में स्पेशल वर्लॉज आया है, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी अपने जवाब में इसका समर्थन या असमर्थन कर सकती हैं, कि असम का 738 एकड़ भूमि बंगलादेश के पास एडवर्स पोजेशन के रूप में था। प्रिंसिपल के मुताबिक यह भूमि बंगलादेश के पास जाना चाहिए। दूसरे राज्यों में यही हुआ है,

तेकिन असम के केस में, आज असम को उस एडवर्स पजेशन से 478 एकड़ भूमि मिली है।... (व्यवधान) आप तथ्य में जाइए।

तीसरा ह्यूमैनिटेरियन टाभ है। कुछ लोग, जो न भारत के हैं, न बंगलादेश के हैं, उनको किसी तरह की कानूनी सुविधाएँ, जो मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती हैं, आज उनको वह सहायता मिल गयी है। उनको इंफ्रस्ट्रक्चर मिल गया है।

चौथा टाभ सिक्वोरिटी का हुआ है। मैंने कहा कि छः किलोमीटर की अन-डिमाकैटेड बाउंड्री है। वया हम नहीं चाहते कि अपनी बाउंड्री को डिमार्क करें, ताकि हम उस पर फेंसिंग कर पाएं। सिक्वोरिटी की टैरिटे से हम भारत की बाउंड्री को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए असम में जो अन-डिमाकैटेड बाउंड्री थी, उस तातटिटीता और डुमाबाड़ी बाउंड्री के डिमार्क होने के बाद असम को 714 एकड़ भूमि और मिली है। साथ ही साथ, असम को जो कुल भूमि मिली है, यह मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि 1240 एकड़ भूमि है अब बाउंड्री पर हम फेंसिंग कर पाएंगे और इससे भारत को लाभ होगा।

फिर पूछन उठता है कि हम क्यों इस पर राजनीति कर रहे हैं? क्यों हमने इस बिल का असमर्थन किया? जहां पर हमें दिखाता है कि बाउंडरी की फेंसिंग हो पाएगी, जहां दिख रहा है कि बांग्लादेश से लैण्ड हम वापस ला रहे हैं, जहां पर यह दिखाता है कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती और गहरी होगी, तो क्यों वहां हम राजनीति कर रहे हैं? क्यों हमने पहले उसका अपोज किया, अब समर्थन कर रहे हैं। पहले असम को उसमें से निकाला, अब असम को उसमें शामिल कर रहे हैं। जब यह देखा जा रहा है कि सभी का लाभ होता है, तब यह पूछन उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? खुद सरकार ही इसका उतर दे पाएगी। आज यह बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, आज हम सभी को इस पर गौरव करना चाहिए। आज हमें प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री श्रीमती सुश्री सुष्मा स्वराज जी को बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय हित में इस बिल को प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय हित में यह बिल लाए हैं, स्टेट बीजेपी ने चाहे जो कहा हो, लेकिन राष्ट्रीय हित में उन्होंने यह निर्णय लिया है। हम उनका स्वागत करते हैं और हम भी सहमत हैं कि अगर हमारे पड़ोसी देश में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वह धर्म के कारण हो, संस्कृति के कारण हो या भाषा के कारण हो, तो उन लोगों भारत द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह हमारा दायित्व बनता है। पूरे दक्षिण एशिया में भारत सर्वश्रेष्ठ देश है। हमारा दायित्व है कि हम सिर्फ अपने देश की इकोनोमी के बारे में नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया को, अपने पूरे नेबरहुड को तीडरशिप दें। सभी देशों की शांति और स्टेबिलिटी में हमारा ही लाभ है। हम चाहते हैं कि आज यह एक ऐतिहासिक दिन है, हम सभी को इस पर गौरव करना चाहिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, सलमान खुर्शीद जी को और धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को और विदेश मंत्री श्रीमती सुश्री सुष्मा स्वराज जी को।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री राजेन गोहेन (नौगोंग) : अध्यक्ष महोदया, आज लैण्ड डील के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसको समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो लैण्ड डील हो रही है, अगर यह लैण्ड डील देश की सुरक्षा को सामने रखकर की गयी है तो सबसे अच्छी और सही बात है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आज यहाँ जिस तरह से चर्चा हो रही है, जिस तरह से बांग्लादेशियों के प्रति हम सद्भावना एवं सिम्पैथी दिखा रहे हैं, आज इन्हीं बांग्लादेशियों के कारण असम में असमीज लोगों का क्या हाल हो रहा है, उसके प्रति आज तक किसी ने कोई सिम्पैथी नहीं दिखाई। असम आज खुद बांग्लादेश का एक एनक्लेव बन गया है। उस एनक्लेव को कैसे हटाएंगे, यह भी आज इस सदन को सोचना होगा।... (व्यवधान) एक नेबरिंग कंट्री को हमें कमजोर नहीं सोचना चाहिए। आज यहाँ हमारी जी है, वह प्रो-इंडिया है, लेकिन कल जब खालिदा जिला आ जाएगी, तब यही हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।... (व्यवधान) इसलिए हमें सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजन जी, आप इधर देखकर अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

श्री राजेन गोहेन : मैडम, इसलिए मैं सदन से यही विनती करूँगा कि यह लैण्ड डील की गयी है, ठीक है, इसके लिए बाउंडरी सेटलमेंट होना चाहिए और बाउंडरी का परमानेंट डिमार्केशन हो जाना चाहिए। इसके साथ-साथ अपने देश की सुरक्षा भी परमानेंट होनी चाहिए। जब तक देश की सुरक्षा परमानेंट नहीं होगी, सिर्फ लैंड डील ही होगी, उनके प्रति सिम्पैथी दिखाकर यह डील करने तो हमारे लिए कल भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बांग्लादेशियों से मुक्ति मिलने के लिए असम के लोगों ने छः साल आन्दोलन किया है और 855 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन आज तक मुक्ति मिली नहीं। कांग्रेस ने जिस तरह से हमें आडवाँतू का हिस्सा बना दिया, उससे निकलना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए अब हमारी सरकार को, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है।... (व्यवधान) आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास से असम के लोगों को बोला था कि असम को बांग्लादेशियों से मुक्त कराएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से निकालने के सवाल पर किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लैंड डील की गई है, हमें थोड़ी कम जमीन मिली और उन्हें ज्यादा जमीन मिली, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। असम बांग्लादेशियों का एक इन्क्लेव बन गया है, लेकिन कल कहीं ऐसा न हो कि किसी दूसरे हिस्से में एक और इन्क्लेव बन जाए। इसलिए उसके प्रति भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अच्छा पड़ोसी तो चाहिए, लेकिन हम अपने घर पर कब्जा करने के लिए पड़ोसी को नहीं

कह सकते और न ही उसे देने की बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हमारे अक्ले सम्बन्ध हों, लेकिन हमें उससे बतकर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि असम को बताना है। यह काम सिर्फ हमारी सरकार ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो कभी ऐसा किया नहीं।... (व्यवधान) असम को बर्बाद करने वाले यही हैं, सारे असम को बर्बाद कर दिया। इसलिए इस लैंड सेटलमेंट की बात पर मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि बांग्लादेशियों को असम से बाहर निकालकर असम को सुरक्षित बनाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती सुश्री सुष्मा स्वराज : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इस पर कांग्रेस पार्टी के श्री अधीर रंजन चौधरी से लेकर बीजेपी के राजेन गोहेन सहित कुल 16 सांसदों ने भाग लिया है। मैंने चर्चा के लिए इस बिल को प्रस्तुत करते समय एक प्रार्थना की थी कि राज्य सभा में यह बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ, अगर वैसी सद्भावना यहाँ भी बनेगी तो एक अच्छा संदेश बांग्लादेश को जाएगा। मैं यह कह सकती हूँ कि एक सांसद ए.यू.डी.एफ. के श्री सिराजुद्दीन अजमत ने बिल के विरोध में बात कही, बाकी सभी ने अपनी-अपनी बातें कहीं और कुल मिलाकर इस बिल का समर्थन किया है।

दो भाषाण तो इतने भावुकतापूर्ण हुए हैं कि सारे सांसद सुनकर भाव-विभोर हो गए, भाई सुगत बोस जी का और अहलुवालिया जी का, मैं यह भी कहना चाहूँगी, शायद आप अंदर सुन रही होंगी टी.वी. पर कि शायद यह पहली चर्चा है जिसमें राजनीति के साथ-साथ संगीत की स्वरलहरियाँ भी बड़ी हैं। अहलुवालिया जी ने और सुगत बोस जी ने तो कविता सुनाई ही थी, लेकिन बाद में मोहम्मद सलीम भाई ने भी उसमें एक कविता जोड़ी। बांग्लादेश की जो अच्छी और श्रेष्ठ रचनाएँ हैं, वे यहाँ इस बिल के संदर्भ में रखी गईं। कुछ सांसदों ने कुछ पूछन उठाए हैं, कुछ ने कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं और कुछ ने सुझाव दिए हैं।

जहाँ तक अधीर रंजन चौधरी जी का सवाल है, मुझे थोड़ा सा दुःख जरूर हुआ क्योंकि उन्होंने जो बात कही, जिस भाव से मैंने बिल को रखा था, उस भाव को वह समझे नहीं। मैंने स्वयं इंदिरा-मुजीब समझौते का जिक्र किया था। मैंने स्वयं डॉ. मनमोहन सिंह और श्रेष्ठ हसीना के प्रोटोकॉल का जिक्र किया। हम इस बिल के पहले विरोध में थे, क्योंकि हम इसे असम के हित की अनदेखी मानते थे, उसका जिक्र मैंने स्वयं किया। लेकिन सर्वसम्मति बनाने के लिए हमने असम को शामिल किया, इसका भी जिक्र किया। ये सारी बातें बहुत ही पारदर्शिता के साथ मैंने प्रारम्भ में ही रख दी थीं, फिर भी उन्होंने अपना पहला वाक्य कहा कि मैं सदन को गुमराह कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कौन सी बात मेरी सदन को गुमराह करने वाली लगी। पूरा इतिहास खोलकर जैसे-जैसे जो चीज हुई थी, उसे मैंने चर्चा के लिए रखते समय कह दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि आधार कार्ड उनको मिलना चाहिए, जन-धन योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए, राशन कार्ड उनको मिलने चाहिए। मैं अधीर बाबू को कहना चाहूँगी कि ये सारे सुझाव राज्य सरकार पूरे करेगी। लेकिन उसके लिए जो धनराशि की आवश्यकता है, आपने टेम्पर्री रिट्रीफ कैम्प की बात की, उसके लिए धनराशि हमने पश्चिम बंगाल सरकार को देने का काम किया है और उनके साथ हमारा जो समझौता हुआ है, जैसा मैंने कहा था कि उन्होंने 3008 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा, उसमें से 775 करोड़ रुपये ऐसा है जो फिक्स एवसर्पेंडिचर होगा, जो इंफ्रस्ट्रक्चर बनाने के लिए होगा, एनक्लेवस में और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आकर लोग बसेंगे। बाकी 2234 करोड़ रुपये परिवर्तनीय है, वैरिबल है, जो इस पर आधारित होगा कि कितने लोग आएंगे। जैसा मैंने कहा कि 3500 से 35000 तक का आकलन है तो 35 हजार को सामने रखकर यह पैकेज तय किया गया है। राशि देने का काम सरकार ने माना है। गृह मंत्रालय को उसकी नोटल एजेंसी बनाया गया है। लेकिन जो चीजें आप चाह रहे हैं कि हों, वे राज्य सरकार के द्वारा होंगी।

उसके बाद एक विधायक आया जो पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं था। सी.के. रामचन्द्रन जी अन्ना-डीएमके की तरफ से बोले। उन्होंने कचतितु का पूछन उठाया। उनका पूछन इस मायने में प्रसंगिक हो

जाता है कि बेरूबाड़ी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जिसमें उन्होंने यह बात कही है कि जब भी भारत का कोई भू-भाग किसी दूसरे देश को ट्रांसफर होता है तो उसमें संविधान संशोधन जरूरी है। दोनों सदन संविधान संशोधन पारित करें और आधे राज्य उसका अनुमोदन करें, तभी लागू होता है... (व्यवधान)

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Without making any amendment, you have made that agreement.... (Interruptions)

श्रीमती सुशमा स्वराज : कवचित्तु में ऐसा हुआ था। वह सदन के पटल पर रख दिया गया था। उसमें संविधान संशोधन नहीं हुआ था। इसलिए इन लोगों का कहना है कि जब हम बांग्लादेश के साथ टैरिस्ट्री ट्रांसफर कर रहे हैं और संविधान संशोधन कर रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं हुआ? मैं बताना चाहूंगी कि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता और दूसरे मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है और मैटर सबजुडिस है। इसलिए सबजुडिस मैटर पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका हमने नोट लिया है।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Hon. Speaker, just now our External Affairs Minister said that my leader Amma also filed a case in the Supreme Court. That is a fact. What is the stand of the Central Government? When the Central Government is filing the affidavit, it is going against that. That is what we raise. It was not passed by the Parliament. What has happened is a legal thing. Therefore, you said that both the Houses have to pass whatever we have done, especially territorial issues. If they are giving anything from our country to the other country, it has to be done. We are doing like that. The External Affairs Ministry is filing the affidavit, it is filing the affidavit in a different way. Even the Supreme Court observed this. That is what we are raising. Please instruct your people to rectify that.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Hon. Deputy-Speaker, I told that the matter is *sub judice*. Therefore, I cannot answer that matter in this House, especially in this regard when we are talking about the land boundary agreement with Bangladesh. So, that question is not relevant. It was relevant in one sense only and, I think, I have already answered that.

उसके बाद जब चर्चा आई तो उसमें दो पृष्ठ आए जिनमें चिंता व्यक्त की गई है। हमारे यहां से विनायक राउत जी और रविन्द्र जेना ने अपनी चिंता व्यक्त की है। इन दोनों ने अवैध घुसपैठ की भी बात कही है। विनायक जी ने गृह मंत्री जी के उत्तर का उल्लेख करते हुए कहा है कि हमारी सीमा पर 88 फीसदी फेंसिंग हुई है, बाकी की नहीं हुई है। इसका समाधान इसमें लिखा है। मैं विनायक जी और रविन्द्र जी दोनों से कहना चाहूंगी कि 88 परसेंट भूमि पर फेंसिंग क्यों हुई है और बाकी पर फेंसिंग का काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी की भूमि की सीमा निर्धारित ही नहीं थी। जब लैंड बाउंड्री तय हो जाएगी तो बाकी की सीमा भी फेंसिंग हो जाएगी। यहां फेंसिंग न होने के कारण, सीमा पर किसी तरह की बाधा न होने के कारण आबाद रूप से, अवैध रूप से लोग आते हैं, यह रूकेगा। इसलिए उसका समाधान इसी में लिखा है जो बिल हम ले कर आ रहे हैं।

श्रीमती के. कविता ने अपनी बात कहते हुए सदन में दो बातें रखीं। उन्होंने कहा कि मेरीटाइम बाउंड्री सैटलड नहीं है, यह बाउंड्री सैटलड है। महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको और सभी को बताना चाहती हूँ कि 7 जुलाई, 2014 को मेरीटाइम बाउंड्री भी बांग्लादेश के साथ सैटलड हो गई है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में यह मामला गया था, आर्बिट्रेशन के माध्यम से एक अवार्ड आ गया जो 7 जुलाई, 2014 को आ गया और जब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का अवार्ड आता है तो वह बाइंडिंग होता है और यह तय होता है कि जो जिसे मिला है, वह उसे स्वीकार करेगा। हमारी मेरीटाइम बाउंड्री सैटलड हो गई है। जहां तक नदियों का सवाल है, वह मामला अभी चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा मामला तिरता नदी का है और दूसरी नदियों का भी है। जहां तक नदियों का मामला है, नदी जल का विवाद अभी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हमने इसे निपटारा है, हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की एक आम सहमति पश्चिम बंगाल के साथ बनाकर हम उसमें कुछ कर पायें। लेकिन अभी तक वह विवाद जिंदा है, परंतु हमारी मेरीटाइम बाउंड्री सैटलड हो गई है।

दूसरी बात आपने कही कि हमें बिग ब्रदर का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, बड़े भाई वाला। मैं कविता जी को बताना चाहूंगी कि हिंदी में शब्द एक ही है बड़े भाई, अंग्रेजी में दो तरह से कहा जाता है, एक है बिग ब्रदर और दूसरा एल्डर ब्रदर। जो बिग ब्रदर का एटीट्यूड है, वह एग्रेसिव का प्रतीक होता है, इसलिए उसे एग्रेसिव कहते हैं। एल्डर ब्रदर केरिग होता है और इसलिए मैं यहां सदन में खड़े होकर कहना चाहूंगी कि भारत का एटीट्यूड हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ बिग ब्रदर का नहीं है, एल्डर ब्रदर का है, जो भारत की संस्कृति है। भारत में बड़ा भाई बहुत केयर करने वाला, ध्यान रखने वाला होता है तो हम जब भी अपना एटीट्यूड रखेंगे, केवल एल्डर ब्रदर का रखेंगे, बिग ब्रदर का एटीट्यूड हम नहीं रखेंगे... (व्यवधान) India is reflected by the Prime Minister. Hence, it is 'he', not 'she'.

अध्यक्ष जी, मॉ. सलीम साहब ने हम पर एक आरोप लगा दिया कि उन्होंने ढाई महीने के अंदर रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन हमने सवा चार महीने लगा दिये। मॉ. साहब यह सच नहीं है। एक सितम्बर को कमेटी गठित हुई, हमने 16 सितम्बर को यह बिल आपके दिया, आपने एक दिसम्बर को रिपोर्ट दे दी, ढाई महीने में आपने बिल्कुल काम पूरा कर दिया। लेकिन एक दिसम्बर को जब वह रिपोर्ट यहां टेबल हुई तो उसके 19 दिन के बाद 19 दिसम्बर को सत्र समाप्त हो गया और आपने इस बिल को लाने से पहले हमसे बहुत अपेक्षाएं की थीं। स्टैंडिंग कमेटी ने यह वादा था कि हम पश्चिम बंगाल के साथ पैकेज भी तय कर लें। आपने यह वादा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी देख लें। इतना काम आपने हमें करने के लिए कहा था, जो उस सत्र की समाप्ति से पहले नहीं हो सकता था, 19 दिसम्बर को सत्र समाप्त हो गया। उसके बाद सत्र फरवरी में आया और वह बजट सत्र आया, जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद रेल बजट और उसके बाद जनरल बजट आता है और उसके बाद रियेस आती है। ये सारा समय और यह अंतराल हमने इसमें लगाया कि हम पश्चिम बंगाल के साथ पैकेज तय कर लें, बाकी चीजें तय कर लें और इस बिल को एक ऐसे रूप में ला सकें, जिससे सर्वसम्मति बन सके। इसीलिए मैंने डा. शशि थरूर जी से उसी दिन कह दिया था कि बजट सत्र के दूसरे खंड में हम इस बिल को ले आयेंगे और मुझे यह लगता है कि अपने पूरे वचन की पूर्ति करते हुए हम इसे यहां ले आये हैं तो जो सवा चार महीने की देरी आपको लग रही है, वह देरी हमारे पार्ट पर नहीं हुई है।

जहां तक गौरव गोर्गोई का सवाल है, यह ठीक है कि हमारे यहां से असम के सांसदों ने राष्ट्रीय हित में बिल का समर्थन किया है। लेकिन अपने असम की व्यथा श्री आर.पी.शर्मा ने भी कही और श्री राजेन गोहेन ने भी कही। लेकिन गौरव जी आपने जो बात कही है, वह ठीक है कि 738 एकड़ जमीन असम के एडवर्स प्रजेसन में थी। इस समझौते में 470 एकड़ जमीन हमारे पास आई है, 268 एकड़ जमीन नहीं आई है। जिस समय प्रोटोकॉल साइन करने के लिए मुख्य मंत्री, श्री तरुण गोर्गोई गये थे, तब वह इसे स्वीकार करके आए थे कि 470 एकड़ हमारे पास आएगी और 268 एकड़ उनके पास जायेगी। लेकिन उसके बाद लौटने पर जब उन्होंने असम की जनभावना देखी और उन्हें यह लगा कि असम में इस चीज का विरोध हो रहा है कि हमारी 268 एकड़ जमीन क्यों जा रही है तो बीच में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भी पूरी की पूरी भूमि लेने की बात की और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। आपने चूंकि पूछा उठाया है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। यह एक आर्टिकल है, जो कि हमारे द्वारा लिखा हुआ नहीं है, जिसमें यह लिखा गया है -

The Chief Minister Tarun Gogoi has recently stated that the State Government cannot support the Agreement until Bangladesh returns the land to Assam currently under its occupation. That means, 738 acres. Significantly, Gogoi was also present with the then Prime Minister, Manmohan Singh when the Agreement was signed in Dhaka. After his return from Bangladesh, he had also expressed his satisfaction over the Agreement but now he is retracting from his earlier stand. On being questioned about the LBA, the Chief Minister sought to know about the steps being taken by the Narendra Modi Government to bring back Assam's land under Bangladesh occupation.

इसलिए एक समय ऐसा आया, जब यह लगा कि असम की जनभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री भी यह वादा रहे हैं कि यह 738 की 738 एकड़ भूमि हमारे पास आनी चाहिए। तब मैंने प्रधान मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि एक रास्ता निकल सकता है कि हम असम को एक तरफ रखकर इस बिल को आगे बढ़ायें, ताकि कम से कम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय का मामला तो सैटल हो। यह जो असम वाला है, इसको रीनिगोशिएट करें। रीनिगोशिएशन में हमें सफलता मिलती या नहीं मिलती, यह मैं नहीं कह सकती पूरी मिलती, आंशिक मिलती, लेकिन असम के हित में ही हमने असम को अलग रखने का फैसला किया था। लेकिन जब मैंने कांग्रेस नेतृत्व से बात की, यहां शशि थरूर जी और यहां गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जी से बात की तो उन्होंने कहा कि वे इंटरनल पार्टी मीटिंग के बाद बताएंगे। बाद में उन्होंने हमसे कहा कि चीफ मिनिस्टर से हमारी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि आप असम अलग क्यों रख रहे हैं? मैंने कहा कि अब असम के सारे राजनीतिक दल एक साथ हो गए हैं, यहां के मुख्य मंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने जा कर बात की और वापस मुझे बताया कि नहीं! मुख्य मंत्री ऑन बोर्ड हैं, मुख्य मंत्री आपको पत्र भी लिखेंगे और हम आपसे कह रहे हैं कि आप असम को शामिल कर के लाइए तभी समर्थन मिलेगा और उसके बाद उनका पत्र आया। ... (व्यवधान) मैं वही तो कह रही हूँ कि उनके कहे मुताबिक जो उन्होंने कहा था कि पत्र आया, पत्र आया और प्रधान मंत्री जी को उन्होंने अलग लिखा, मुझे अलग लिखा और आखिरी सेंटेंस यह था कि "I would request you once again to take steps so that the aforesaid protocol is ratified by the Parliament by including the clauses relating to Assam." जब मुख्य मंत्री का यह पत्र आ गया, कांग्रेस नेतृत्व

से बात हो गई और बाकी दलों ने भी यह कहा कि सर्वसम्मति बनाने के लिए आप असम को शामिल ही कर लें तो ठीक है, तो खुद प्रधान मंत्री जी ने मुझे कहा कि देखिए जनतंत्र में सदन की भावना जनभावना का ही प्रतिबिंब होती है। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम असम को शामिल कर के चलें। फिर हमने असम को इसमें शामिल कर लिया और एक सर्वसम्मति बनाने की दृष्टि से हम लोग यहां आए। मैंने कोई चीज इसमें छुपाई नहीं थी। आपने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है कि 738 एकड़ में से 470 एकड़ आ रही हैं, 268 एकड़ नहीं आ रही हैं। हमारे तिरुपति के एक सांसद श्री वासुदेव राव जी ने पूछा था कि कुल ज़मीन कितनी जा रही है? कुल ज़मीन हमें जो एडवर्स पोज़ेशन में है, वह 2777 एकड़ हमारे पास रहेगी, 2267 उनके पास जाएगी, हमें 510 एकड़ ज्यादा मिल रही है, यह तो एडवर्स पोज़ेशन का मामला है। जो इन्वलेक्स का मामला है, आपने अखबार में बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि उसमें 10 हज़ार एकड़ जा रही हैं। हमारे पास से 17 हज़ार जा रही हैं और उनके पास से 7 हज़ार आ रही हैं। लेकिन वह जो 10 हज़ार एकड़ है, राव जी, वह बिल्कुल नोशनल है। गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वे इन्वलेक्स बिल्कुल अंदर हैं। उनमें एवसेस नहीं है, हम यहां तक पहुंच नहीं सकते हैं और जो आपने कहा कि सीमाएं थ्रिक हो रही हैं, वह सीमा पर नहीं है, उन इन्वलेक्स की अदला-बदली के कारण, सीमा नहीं बदल रही है, वह तो अंदर है, भारत के भी बहुत अंदर है और बांग्लादेश वाले भी बहुत अंदर हैं। इसलिए उससे सीमा नहीं सिकुड़ रही है। लेकिन हॉल नोशनल तौर पर 10 हज़ार एकड़ ट्रांसफर हो रही है, जो एडवर्स पोज़ेशन में लैण्ड है, उसमें 510 एकड़ हमें ज्यादा मिल रही है। यह ज़मीन का मामला है। गौरव जी ने कहा कि हम इसे डॉक्यूमेंटेशन कर दें और यह बता दें कि क्या-क्या हम इसमें देना चाह रहे हैं, यह एक अच्छा सुझाव है, हम लोग ज़रूर इसमें डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे ताकि यह भी पता चल जाए कि इन्वलेक्स में कितनी-कितनी ज़मीन है, एडवर्स पोज़ेशन में कितनी-कितनी ज़मीन कहां-कहां कैसे-कैसे जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि एडवर्स पोज़ेशन में यह तय किया गया कि जिसके पास जिसका कब्ज़ा है, उतना रख तो और वह हर जगह हमें हमारा कब्ज़ा ज्यादा मिला। पश्चिम बंगाल में भी हमें ज्यादा मिल रही है, त्रिपुरा में भी ज्यादा मिल रही है, मेघालय में भी ज्यादा मिल रही है, लेकिन असम में उनके ऑक्जुपेशन में 738 एकड़ थी, जिस पर समझौता हुआ है कि 470 एकड़ हमारे पास आएगी और 268 एकड़ उनके पास जाएगी, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर देंगे, बल्कि हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा कि सारे सांसदों को पता चल जाएगा।

अब मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि पूछा यही था और चिंताएं भी यही थीं। मुझे नहीं लगता कि एक भी पूछा इसमें अनुरोधित रहा है। सबके पूछों का उत्तर मैंने दे दिया है। सिराजुद्दीन साहब ने एयूडीएफ की तरफ से यह बात कही है कि मैं बिल को विट्टिंग करूँ तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बिल तो हम लोग विट्टिंग नहीं कर रहे हैं। आपने सदन की भावना भी देखा ली है, लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन होगा कि आपको जो अपनी बात कहनी थी, वह कह दी, वह प्रोसिडिंग्स में दर्ज भी हो गई है। अगर हम वोटिंग के समय यह बात दिखा दें कि एक भी वोट खिलाफ नहीं गया है, जैसे मैंने कहा था कि राज्य सभा में एक भी पीटा बटन नहीं दबा, कोई एक्सटेंशन नहीं थी, एक भी लाल बटन नहीं दबा, कोई भी नो नहीं था, अगर यहां भी यह बिल इसी तरह से पारित हो जाए कि केवल आइज़ ही आइज़ हों तो बांग्लादेश को ही नहीं हमारे पड़ोसी देशों को भी और विश्व को भी एक बहुत बढ़िया संदेश जाएगा कि इस तरह के मसलों पर भारत में राजनैतिक दलों में कोई विमत नहीं होता है, बल्कि सब एक साथ केवल सार्द्ध हित में सोचते हैं, सार्द्ध हित में फैसला करते हैं। इसी विनम्र निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

SHRI GAURAV GOGOI : Madam Speaker, I need a small clarification.

माननीय अध्यक्ष : अब तो बहुत बात विलयर हो गई है।

SHRI GAURAV GOGOI : Madam, I have a clarification regarding the acreage of land gained by Assam. The hon. Minister of External Affairs was very right in talking about the land under adverse possessions where Bangladesh had 738 acres of land under adverse possession which belongs to Assam. More than 470 acres, under adverse possession, will be brought back to Assam. Is it also correct that after formalizing the undemarcated boundaries in Assam within Lathitilla-Dumabari area Assam will further gain in addition to 470 acres under adverse possession? After finalizing the undemarcated boundaries in Lathitilla-Dumabari area, will Assam gain further 714 acres of land, as stated by MEA documentation? Thereby the total gain of land to Assam is 1240 acres. Will the hon. Minister clarify this because these are land records? We wanted to be stated that the land that Assam gains from adverse possession and the land that Assam gains from finalizing the undemarcated boundaries.

श्रीमती सुष्मा स्वराज : गौरव जी, जो बात वहाँ विरोध की हुई, वह अकेले एडवर्स पोज़ेशन के बारे में हुई कि 738 एकड़ में से 470 मिल रही हैं, 268 उधर जा रही हैं। उस 268 को लेकर आन्दोलन हो रहा था। इसलिए मैंने यह बात कही, जो बाकी बात आप कह रहे हैं कि अनडिमांटेड बाउन्ड्रीज डिमांटेड हो जाने के बाद मिलेगी, वह सही है। लेकिन जो विरोध था वह उन 268 एकड़ को लेकर था, जो एडवर्स पोज़ेशन में हमें कम मिल रही थी... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो-नो, एक के बाद एक इतने वलेंटिफिकेशन नहीं होते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, before I put the Motion for Consideration to the vote of the House, I may inform the House that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIYA NAIDU): Madam, we have to remind the hon. Members to sit in their respective seats. Then, only their votes will be recorded.

HON. SPEAKER: The voting on another Bill has already taken place in the afternoon. Yesterday also they had voted. I think, everybody knows how to vote and from where to vote.

Let the lobbies be cleared-

HON. SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

Hon. Members, you all know as to how to vote and everything. So, no instructions are necessary.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India to give effect to the acquiring of territories by India and transfer of certain territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the Governments of India and Bangladesh, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 1 AYES 17:47 Hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.
Chaudhary, Shri Haribhai
Chaudhary, Shri P.P.
Chaudhary, Shri Pankaj
Chaudhary, Shri Ram Tahal
Chaudhary, Shri Santokh Singh
Chaudhury, Shri Jitendra
Chauhan, Shri P. P.
Chautala, Shri Dushyant
Chavan, Shri Harishchandra
Chavda, Shri Vinod Lakhmashi
Chhewang, Shri Thupstan
Chhotelal, Shri
Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara
Choubey, Shri Ashwini Kumar
Choudhary, Shri Birendra Kumar
Chouhan, Shri Nandkumar Singh
Chudasama, Shri Rajeshbhai
Danve, Shri Raosaheb Patil
Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh
□Datta, Shri Sankar Prasad
Dattatreya, Shri Bandaru
Deka, Shri Ramen
Dev, Kumari Sushmita
Devi, Shrimati Rama
Devi, Shrimati Veena
Dharambir, Shri
Dhotre, Shri Sanjay
Dhruvanarayana, Shri R.
Dhurve, Shrimati Jyoti
Dohre, Shri Ashok Kumar
Diwakar, Shri Rajesh Kumar
Dubey, Shri Nishikant
Dubey, Shri Satish Chandra
Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish
*Elumalai, Shri V.
Gaddigoudar, Shri P.C.
Gaikwad, Dr. Sunil Baliram
Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal
Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay
Gangwar, Shri Santosh Kumar
Gautam, Shri Satish Kumar
Geete, Shri Anant Gangaram
Ghosh, Shrimati Arpita
Giluwa, Shri Laxman
Gogoi, Shri Gaurav
Gopal, Dr. K.
Gopalakrishnan, Shri C.
Gopalakrishnan, Shri R.
Gowda, Shri D.V. Sadananda
Gowda, Shri S.P. Muddahanume
Gupta, Shri Sudheer
Gurjar, Shri Krishanpal
Hansdak, Shri Vijay Kumar
*Hari, Shri G.
Haribabu, Dr. Kambhampati
Hooda, Shri Deepender Singh
*Jadhav, Shri Sanjay Haribhau
Jaiswal, Dr. Sanjay
Jardosh, Shrimati Darshana Vikram
Jat, Prof. Sanwar Lal
Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh
Jayavardhan, Dr. J.
Jigajinagi, Shri Ramesh
Joshi, Dr. Murli Manohar
Joshi, Shri Chandra Prakash
Joshi, Shri Pralhad
Jyoti, Sadhvi Niranjana
Kalvakuntla, Shrimati kavitha
Kamaraj, Dr. K.
Karandlaje, Kumari Shobha
Karunakaran, Shri P.
Kashyap, Shri Dinesh
Kashyap, Shri Virender
Kaswan, Shri Rahul
Kataria, Shri Rattan Lal
Kateel, Shri Nalin Kumar
Kaushik, Shri Ramesh Chander

*Khan, Shri Md. Badaruddoza
Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.
Khanna, Shri Vinod
*Kharge, Shri Mallikarjun
Khuba, Shri Bhagwanth
Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu
Kishore, Shri Jugal
Kishore, Shri Kaushal
Koli, Shri Bahadur Singh
Koshiyari, Shri Bhagat Singh
Kristappa, Shri N.
Kulaste, Shri Faggan Singh
Kumar, Dr. Virendra
Kumar, Kunwar Sarvesh
Kumar, Shri Dharmendra
Kumar, Shri K. Ashok
Kumar, Shri Kaushalendra
Kumar, Shri P.
Kumar, Shri Shanta
Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai
Kushawaha, Shri Ravinder
Lekhi, Shrimati Meenakashi
Lokhande, Shri Sadashiv
Maharaj, Dr. Swami Sakshiji
Mahato, Dr. Banshilal
Mahato, Dr. Mriganka
Mahato, Shri Bidyut Baran
Mahtab, Shri Bhartruhari
Mahendran, Shri C.
Majhi, Shri Balbhadra
Mandal, Dr. Tapas
Manjhi, Shri Hari
Marabi, Shri Kamal Bhan Singh
Maragatham, Shrimati K.
Maurya, Shri Keshav Prasad
Meena, Shri Arjun Lal
Meena, Shri Harish
 Meghwal, Shri Arjun Ram
Mishra, Shri Anoop
Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

*Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Naik, Shri Shripad Yesso

□Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

*Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paraste, Shri Dalpat Singh

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai
Patel, Shri Prahlad Singh
Patel, Shri Subhash
Patel, Shrimati Jayshreeben
Pathak, Shrimati Riti
Patil, Shri C. R.
Patil, Shri Kapil Moreshwar
Patil, Shri Sanjay Kaka
Patole, Shri Nana
Phule, Sadhvi Savitri Bai
Poddar, Shrimati Aparupa
Prabakaran, Shri K. R. P.
 Prasad, Dr. Bhagirath
Pratap, Shri Krishan
*Premachandran, Shri N.K.
Raajhaa, Shri A. Anwhar
Radhakrishnan, Shri Pon
Radhakrishnan, Shri R.
 Raghavan, Shri M.K.
Rai, Shri Nityanand
Raj, Shrimati Krishna
Rajbhar, Shri Harinarayan
Rajendran, Shri S.
Rajesh, Shri M. B.
Rajoria, Dr. Manoj
Rajput, Shri Mukesh
Raju, Shri Ashok Gajapathi
Raju, Shri Gokaraju Ganga
Ram, Shri Janak
Ram, Shri Vishnu Dayal
*Ramachandran, Shri K. N.
Ramachandran, Shri Mullappally
Rao, Shri M. Venkateswara
Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa
Rathod, Shri D.S.
Rathore, Col. Rajyavardhan
Rathwa, Shri Ramsinh
Raut, Shri Vinayak Bhaurao
Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh
Ray, Shri Bishnu Pada
Ray, Shri Ravindra Kumar
Reddy, Shri J.C. Divakar
Reddy, Shri Konda Vishweshwar
Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan
 Reddy, Shri P. Srinivasa
Reddy, Shri Y. V. Subba
*Renuka, Shrimati Butta
Rijju, Shri Kiren
Rio, Shri Neiphiu
Roy, Prof. Saugata
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Sahu, Shri Chandulal
Sahu, Shri Lakhan Lal
Sai, Shri Vishnu Dev
Saini, Shri Rajkumar
Salim, Shri Mohammad
Samal, Dr. Kulmani
Sampla, Shri Vijay
Sampath, Dr. A.
*Sanghamita, Dr. Mamta
Sanjar, Shri Alok
Saren, Dr. Uma
Sarmah, Shri Ram Prasad
Sarswati, Shri Sumedhanand
Satav, Shri Rajeev
Sathyabama, Shrimati V.
Satpathy, Shri Tathagata
Sawaikar, Adv. Narendra Keshav
Sawant, Shri Arvind
*Senthilnathan, Shri P. R.
Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi
 Shanavas, Shri M.I.
Sharma, Dr. Mahesh
Shekhawat, Shri Gajendra Singh
Shetty, Shri Gopal
Shewale, Shri Rahul
Shinde, Dr. Shrikant Eknath
Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.
Siddeshwara, Shri G. M.
Sigriwal, Shri Janardan Singh
Simha, Shri Pratap
Singh, Dr. Jitendra
Singh, Dr. Nepal
Singh, Dr. Prabhas Kumar
Singh, Dr. Satya Pal
Singh, Dr. Yashwant
Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar
Singh, Kunwar Bharatendra
Singh, Shri Abhishek
Singh, Shri Bharat
Singh, Shri Bhola
Singh, Shri Dushyant
Singh, Shri Ganesh
Singh, Shri Hukum
Singh, Shri Lallu
Singh, Shri Nagendra
Singh, Shri Pashupati Nath
Singh, Shri R. K.
Singh, Shri Rajnath
Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer
Singh, Shri Rakesh
Singh, Shri Ravneet
Singh, Shri Satyapal
Singh, Shri Sunil Kumar
Singh, Shri Sushil Kumar
Singh, Shri Uday Pratap
Solanki, Dr. Kirit P.
Somaiya, Dr. Kirit
Sonkar, Shri Vinod Kumar
Sonker, Shrimati Neelam
Sonowal, Shri Sarbananda
Sriram, Shri Malyadri
Sriramulu, Shri B.
□ Sundaram, Shri P. R.
Suresh, Shri D.K.
Suresh, Shri Kodikunnil
@Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thambidurai, Dr. M.

Tharoor, Dr. Shashi

*Thomas, Prof. K.V.

Tiwari, Shri Manoj

Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Utawal, Shri Manohar

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

NOES

Nil

ABSTAIN

Nil

...(Interruptions)

श्री एम. वैकैर्या नायडू : इनके साथ ही एनाउंस करना होगा, नहीं तो दोबारा करना होगा। एक ही स्लिप है, इसको जोड़कर एनाउंस करें तो बेहतर होगा, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। यह रिकार्ड में जाएगा।

HON. SPEAKER: Subject to further correction[□], the result of the Division is:

Ayes: 320

Noes: 001

Abstain: 000

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.

Clause 2 Definitions

HON. SPEAKER: The House will now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill

Before I put Clause 2 to the vote of the House, I would like to say that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division.

The lobbies are already clear.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 2 AYES 17:51 Hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Kalyan

[□]Banerjee, Shri Prasun

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti
Basheer, Shri E. T. Mohammad
Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai
Bhagat, Shri Bodh Singh
Bhagat, Shri Sudarshan
Bhamre, Dr. Subhash Ramrao
□ Bharathi Mohan, Shri R.K.
Bharti, Sushri Uma
Bhatt, Shrimati Ranjanben
Bhuria, Shri Dileep Singh
Bidhuri, Shri Ramesh
Biju, Shri P. K.
Birla, Shri Om
Bohra, Shri Ramcharan
Bose, Prof. Sugata
Chand, Shri Nihal
Chandel, Kunwar Pushpendra Singh
Chaudhary, Shri C. R.
Chaudhary, Shri Haribhai
Chaudhary, Shri P.P.
Chaudhary, Shri Pankaj
Chaudhary, Shri Ram Tahal
Chaudhary, Shri Santokh Singh
Chaudhury, Shri Jitendra
*Chauhan, Shri P. P.
Chautala, Shri Dushyant
Chavan, Shri Harishchandra
Chavda, Shri Vinod Lakhmashi
Chhewang, Shri Thupstan
Chhotelal, Shri
Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara
Choubey, Shri Ashwini Kumar
Choudhary, Shri Birendra Kumar
Chouhan, Shri Nandkumar Singh
Chudasama, Shri Rajeshbhai
Danve, Shri Raosaheb Patil
Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh
□ Datta, Shri Sankar Prasad
Dattatreya, Shri Bandaru
Deka, Shri Ramen

Dev, Kumari Sushmita
Devi, Shrimati Rama
Devi, Shrimati Veena
Dharambir, Shri
Dhotre, Shri Sanjay
Dhruvanarayana, Shri R.
Dhurve, Shrimati Jyoti
Dohre, Shri Ashok Kumar
Diwakar, Shri Rajesh Kumar
Dubey, Shri Nishikant
Dubey, Shri Satish Chandra
Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish
*Elumalai, Shri V.
Gaddigoudar, Shri P.C.
Gaikwad, Dr. Sunil Baliram
Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal
Gandhi, Shri Rahul
Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay
Gangwar, Shri Santosh Kumar
Gautam, Shri Satish Kumar
Geete, Shri Anant Gangaram
Ghosh, Shrimati Arpita
Giluwa, Shri Laxman
Gogoi, Shri Gaurav
□Gohain, Shri Rajen
*Gopal, Dr. K.
Gopalakrishnan, Shri C.
Gopalakrishnan, Shri R.
Gowda, Shri D.V. Sadananda
Gowda, Shri S.P. Muddahanume
Gupta, Shri Sudheer
Gurjar, Shri Krishanpal
Hansdak, Shri Vijay Kumar
*Hari, Shri G.
Haribabu, Dr. Kambhampati
Hooda, Shri Deepender Singh
Jadhav, Shri Sanjay Haribhau
Jaiswal, Dr. Sanjay
Jardosh, Shrimati Darshana Vikram
Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjana

□ Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Dinesh

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

*Khan, Shri Md. Badaruddoza

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.

Khanna, Shri Vinod

Kharge, Shri Mallikarjun

Khuba, Shri Bhagwanth

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu

Kishore, Shri Jugal

Kishore, Shri Kaushal

Koli, Shri Bahadur Singh

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kumar, Dr. Virendra

Kumar, Kunwar Sarvesh

Kumar, Shri Dharmendra

Kumar, Shri K. Ashok

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri P.

Kumar, Shri Shanta

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai

Kushawaha, Shri Ravinder

Lekhi, Shrimati Meenakashi

Lokhande, Shri Sadashiv

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji
Mahato, Dr. Banshilal
Mahato, Dr. Mriganka
Mahato, Shri Bidyut Baran
Mahtab, Shri Bhartruhari
Mahendran, Shri C.
Majhi, Shri Balbhadra
Mandal, Dr. Tapas
Manjhi, Shri Hari
Marabi, Shri Kamal Bhan Singh
Maragatham, Shrimati K.
Maurya, Shri Keshav Prasad
Meena, Shri Arjun Lal
Meena, Shri Harish
Meghwal, Shri Arjun Ram
Mishra, Shri Anoop
Mishra, Shri Bhairon Prasad
Mishra, Shri Daddan
Mishra, Shri Janardan
Mishra, Shri Kalraj
Modi, Shri Narendra
Mohan, Shri M. Murli
Mohan, Shri P.C.
Mohapatra, Dr. Sidhant
Moily, Shri M. Veerappa
Mukherjee, Shri Abhijit
Munda, Shri Karia
Munde, Dr. Pritam Gopinath
Muniyappa, Shri K.H.
Nagar, Shri Rodmal
Nagarajan, Shri P.
Naik, Shri Shripad Yesso
*Narasimham, Shri Thota
Nath, Shri Chand
Natterjee, Shri J.J.T.
Nete, Shri Ashok Mahadeorao
Nishad, Shri Ajay
Nishad, Shri Ram Charitra
Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

*Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paraste, Shri Dalpat Singh

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa

Prabakaran, Shri K. R. P.

Prasad, Dr. Bhagirath

Pratap, Shri Krishan

□ Premachandran, Shri N.K.

Raajhaa, Shri A. Anwhar

Radhakrishnan, Shri Pon

Radhakrishnan, Shri R.

□ Raghavan, Shri M.K.

Rai, Shri Nityanand

Raj, Shrimati Krishna

Rajbhar, Shri Harinarayan

*Rajendran, Shri S.
Rajesh, Shri M. B.
Rajoria, Dr. Manoj
Rajput, Shri Mukesh
Raju, Shri Ashok Gajapathi
Raju, Shri Gokaraju Ganga
Ram, Shri Janak
Ram, Shri Vishnu Dayal
Ramachandran, Shri K. N.
Ramachandran, Shri Mullappally
Rao, Shri M. Venkateswara
Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa
Rathod, Shri D.S.
Rathore, Col. Rajyavardhan
Rathwa, Shri Ramsinh
Raut, Shri Vinayak Bhaurao
Raval, Shri Paresh
Rawat, Shrimati Priyanka Singh
Ray, Shri Bishnu Pada
Ray, Shri Ravindra Kumar
Reddy, Shri J.C. Divakar
Reddy, Shri Konda Vishweshwar
Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan
 Reddy, Shri P. Srinivasa
Reddy, Shri Y. V. Subba
*Renuka, Shrimati Butta
Rijju, Shri Kiren
Rio, Shri Neiphiu
Roy, Prof. Saugata
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Sahu, Shri Chandulal
Sahu, Shri Lakhan Lal
Sai, Shri Vishnu Dev
Saini, Shri Rajkumar
Salim, Shri Mohammad
Samal, Dr. Kulmani
Sampla, Shri Vijay
Sampath, Dr. A.
*Sanghamita, Dr. Mamta

Sanjar, Shri Alok
Saren, Dr. Uma
Sarmah, Shri Ram Prasad
Sarswati, Shri Sumedhanand
Satav, Shri Rajeev
Sathyabama, Shrimati V.
Satpathy, Shri Tathagata
Sawaikar, Adv. Narendra Keshav
Sawant, Shri Arvind
*Senthilnathan, Shri P. R.
Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi
□Shanavas, Shri M.I.
Sharma, Dr. Mahesh
Shekhawat, Shri Gajendra Singh
Shetty, Shri Gopal
Shewale, Shri Rahul
Shinde, Dr. Shrikant Eknath
Shirole, Shri Anil
Shyal, Dr. Bhartiben D.
Siddeshwara, Shri G. M.
Sigriwal, Shri Janardan Singh
Simha, Shri Pratap
Singh, Dr. Jitendra
Singh, Dr. Nepal
Singh, Dr. Prabhas Kumar
Singh, Dr. Satya Pal
Singh, Dr. Yashwant
Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar
Singh, Kunwar Bharatendra
Singh, Shri Abhishek
Singh, Shri Bharat
Singh, Shri Bhola
Singh, Shri Dushyant
Singh, Shri Ganesh
Singh, Shri Hukum
Singh, Shri Lallu
Singh, Shri Nagendra
Singh, Shri Pashupati Nath
Singh, Shri R. K.
Singh, Shri Rajnath

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer

Singh, Shri Rakesh

Singh, Shri Satyapal

Singh, Shri Sunil Kumar

Singh, Shri Sushil Kumar

Singh, Shri Uday Pratap

Solanki, Dr. Kirit P.

Somaiya, Dr. Kirit

Sonkar, Shri Vinod Kumar

Sonker, Shrimati Neelam

Sonowal, Shri Sarbananda

Sriram, Shri Malyadri

Sriramulu, Shri B.

Sundaram, Shri P. R.

Suresh, Shri D.K.

Suresh, Shri Kodikunnil

Swaraj, Shrimati Sushma

Tadas, Shri Ramdas C.

Tamta, Shri Ajay

Tanwar, Shri Kanwar Singh

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar

Teni, Shri Ajay Misra

Thambidurai, Dr. M.

Tharoor, Dr. Shashi

Thomas, Prof. K.V.

Tiwari, Shri Manoj

*Tomar, Shri Narendra Singh

Tripathi, Shri Sharad

Trivedi, Shri Dinesh

Udhayakumar, Shri M.

Usendi, Shri Vikram

Utawal, Shri Manohar

Vanaroja, Shrimati R.

Vardhan, Dr. Harsh

Vasanthi, Shrimati M.

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai

Velagapalli, Shri Varaprasad Rao

*Venkatesh Babu, Shri T. G.

Venugopal, Dr. P.

Venugopal, Shri K. C.

Verma, Dr. Anshul

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh

Verma, Shri Rajesh

Verma, Shrimati Rekha

Vichare, Shri Rajan

Wanga, Shri Chintaman Navasha

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan

Yadav, Shri Om Prakash

Yediyurappa, Shri B.S.

NOES

Nil

ABSTAIN

Nil

HON. SPEAKER: Subject to correction[□], the result of the Division is:

Ayes: 323

Noes: 000

Abstain: 000

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill

Clause 3 Amendment of First Schedule to the Constitution

HON. SPEAKER: Hon. Members, there are seven Government Amendments to Clause 3. Hon. Minister.

संशोधन प्रस्तुत हुआ :

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 और 21 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" के स्थान पर
"संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" के स्थान पर
"संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 और 28 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" के स्थान पर
"संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 और 30 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" के स्थान पर
"संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" के स्थान पर
"संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 38 और 39 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" के स्थान पर
"संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 40 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" के स्थान पर
"संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

(श्रीमती सुआमा स्वराज)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): You have already voted two Clauses. Now, again you are moving it from one to seven together.

HON. SPEAKER: Yes, they will be taken up together.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You could have taken it earlier.

HON. SPEAKER: These are Amendments and not Clauses.

श्रीमती सुआमा स्वराज : खड़े जी, एक ही वलॉज में संशोधन है और उसी में सात लाइनों में संशोधन है। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: These are Amendments to Clause 3.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. Gaurav Gogoi, please go to your seat.

श्रीमती सुआमा स्वराज : केवल एक वलॉज में संशोधन है और वह सात लाइनों में 119वां लिखा है, जिसे 100वां लिखना है। इसलिए सातों संशोधन एक ही वलॉज, वलॉज 3 में हैं और केवल इतना संशोधन है कि 119वां को 100वां किया जाए।

18.00 hrs.

माननीय अध्यक्ष : छ: बज गए हैं। आप सभी की सहमति से सभा की कार्रवाई का समय इस बिल के पास होने तक आगे बढ़ाया जाय?

कई माननीय सदस्य : हां।

HON. SPEAKER: Before I put clause 3, as amended, to the vote of the House, I would like to say that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division.

Now, the Lobbies have already been cleared.

The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

DIVISION NO. 3 AYES 17:55 Hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Baheria, Shri Subhash Chandra

Bais, Shri Ramesh

Bala, Shrimati Anju

Bandyopadhyay, Shri Sudip

Banerjee, Shri Kalyan

Banerjee, Shri Prasun

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti

Basheer, Shri E. T. Mohammad

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai

Bhagat, Shri Bodh Singh

Bhagat, Shri Sudarshan

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao

Bharathi Mohan, Shri R.K.

Bharti, Sushri Uma

Bhatt, Shrimati Ranjanben

Bhuria, Shri Dileep Singh

Bidhuri, Shri Ramesh

Biju, Shri P. K.

Birla, Shri Om

Bohra, Shri Ramcharan

Bose, Prof. Sugata

Chand, Shri Nihal

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh

Chaudhary, Shri C. R.

Chaudhary, Shri Haribhai

Chaudhary, Shri P.P.
Chaudhary, Shri Pankaj
Chaudhary, Shri Ram Tahal
Chaudhary, Shri Santokh Singh
Chaudhury, Shri Jitendra
*Chauhan, Shri P. P.
Chautala, Shri Dushyant
Chavan, Shri Harishchandra
Chavda, Shri Vinod Lakhmashi
Chhewang, Shri Thupstan
Chhotelal, Shri
Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara
Choubey, Shri Ashwini Kumar
Choudhary, Shri Birendra Kumar
Chouhan, Shri Nandkumar Singh
□Chowdhary, Shri Adhir Ranjan
Chudasama, Shri Rajeshbhai
Danve, Shri Raosaheb Patil
Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh
*Datta, Shri Sankar Prasad
Dattatreya, Shri Bandaru
Deka, Shri Ramen
Dev, Kumari Sushmita
Devi, Shrimati Rama
Devi, Shrimati Veena
Dharambir, Shri
Dhotre, Shri Sanjay
Dhruvanarayana, Shri R.
Dhurve, Shrimati Jyoti
Dohre, Shri Ashok Kumar
*Diwakar, Shri Rajesh Kumar
Dubey, Shri Nishikant
Dubey, Shri Satish Chandra
Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish
*Elumalai, Shri V.
Gaddigoudar, Shri P.C.
Gaikwad, Dr. Sunil Baliram
Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal
Gandhi, Shri Rahul

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay

Gangwar, Shri Santosh Kumar

Gautam, Shri Satish Kumar

Geete, Shri Anant Gangaram

Ghosh, Shrimati Arpita

Giluwa, Shri Laxman

Gogoi, Shri Gaurav

Gohain, Shri Rajen

Gopal, Dr. K.

*Gopalakrishnan, Shri C.

Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda

Gowda, Shri S.P. Muddahanume

Gupta, Shri Sudheer

Gurjar, Shri Krishanpal

Hansdak, Shri Vijay Kumar

*Hari, Shri G.

Haribabu, Dr. Kambhampati

Hooda, Shri Deepender Singh

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau

Jaiswal, Dr. Sanjay

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram

Jat, Prof. Sanwar Lal

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh

Jayavardhan, Dr. J.

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Dr. Murli Manohar

Joshi, Shri Chandra Prakash

Joshi, Shri Pralhad

Jyoti, Sadhvi Niranjana

Kalvakuntla, Shrimati kavitha

Kamaraj, Dr. K.

Karandlaje, Kumari Shobha

Karunakaran, Shri P.

Kashyap, Shri Dinesh

Kashyap, Shri Virender

Kaswan, Shri Rahul

Kataria, Shri Rattan Lal

Kateel, Shri Nalin Kumar

Kaushik, Shri Ramesh Chander

*Khan, Shri Md. Badaruddoza
Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.
Khanna, Shri Vinod
Kharge, Shri Mallikarjun
Khuba, Shri Bhagwanth
Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu
Kishore, Shri Jugal
Kishore, Shri Kaushal
Koli, Shri Bahadur Singh
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Kristappa, Shri N.
Kulaste, Shri Faggan Singh
Kumar, Dr. Virendra
Kumar, Kunwar Sarvesh
Kumar, Shri Dharmendra
Kumar, Shri K. Ashok
Kumar, Shri Kaushalendra
Kumar, Shri P.
Kumar, Shri Shanta
Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai
Kushawaha, Shri Ravinder
Lekhi, Shrimati Meenakashi
Lokhande, Shri Sadashiv
Maharaj, Dr. Swami Sakshiji
Mahato, Dr. Banshilal
Mahato, Dr. Mriganka
Mahato, Shri Bidyut Baran
Mahtab, Shri Bhartruhari
Mahendran, Shri C.
Majhi, Shri Balbhadra
Mandal, Dr. Tapas
Manjhi, Shri Hari
Marabi, Shri Kamal Bhan Singh
Maragatham, Shrimati K.
Maurya, Shri Keshav Prasad
Meena, Shri Arjun Lal
Meena, Shri Harish
Meghwal, Shri Arjun Ram
Mishra, Shri Anoop
Mishra, Shri Bhairon Prasad

Mishra, Shri Daddan

Mishra, Shri Janardan

Mishra, Shri Kalraj

Modi, Shri Narendra

Mohan, Shri M. Murli

Mohan, Shri P.C.

Mohapatra, Dr. Sidhant

Moily, Shri M. Veerappa

Mukherjee, Shri Abhijit

Munda, Shri Karia

Munde, Dr. Pritam Gopinath

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Naik, Shri Shripad Yesso

*Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatile, Shrimati Kamla

*Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paraste, Shri Dalpat Singh

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai
Patel, Shri Natubhai Gomanbhai
Patel, Shri Prahlad Singh
Patel, Shri Subhash
Patel, Shrimati Jayshreeben
Pathak, Shrimati Riti
Patil, Shri C. R.
Patil, Shri Kapil Moreshwar
Patil, Shri Sanjay Kaka
Patole, Shri Nana
Phule, Sadhvi Savitri Bai
Poddar, Shrimati Aparupa
Prabakaran, Shri K. R. P.
Prasad, Dr. Bhagirath
Pratap, Shri Krishan
 Premachandran, Shri N.K.
Raajhaa, Shri A. Anwhar
Radhakrishnan, Shri Pon
Radhakrishnan, Shri R.
 Raghavan, Shri M.K.
Rai, Shri Nityanand
Raj, Shrimati Krishna
Rajbhar, Shri Harinarayan
Rajendran, Shri S.
Rajesh, Shri M. B.
Rajoria, Dr. Manoj
Rajput, Shri Mukesh
Raju, Shri Ashok Gajapathi
Raju, Shri Gokaraju Ganga
Ram, Shri Janak
Ram, Shri Vishnu Dayal
Ramachandran, Shri K. N.
Ramachandran, Shri Mullappally
Rao, Shri M. Venkateswara
Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa
Rathod, Shri D.S.
Rathore, Col. Rajyavardhan
Rathwa, Shri Ramsinh
Raut, Shri Vinayak Bhaurao
Raval, Shri Paresh

Rawat, Shrimati Priyanka Singh
Ray, Shri Bishnu Pada
Ray, Shri Ravindra Kumar
Reddy, Shri J.C. Divakar
Reddy, Shri Konda Vishweshwar
Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan
 Reddy, Shri P. Srinivasa
Reddy, Shri Y. V. Subba
*Renuka, Shrimati Butta
Rijju, Shri Kiren
Rio, Shri Neiphiu
Roy, Prof. Saugata
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Sahu, Shri Chandulal
Sahu, Shri Lakhan Lal
Sai, Shri Vishnu Dev
Saini, Shri Rajkumar
Salim, Shri Mohammad
Samal, Dr. Kulmani
Sampla, Shri Vijay
Sampath, Dr. A.
*Sanghamita, Dr. Mamta
Sanjar, Shri Alok
Saren, Dr. Uma
Sarmah, Shri Ram Prasad
Sarswati, Shri Sumedhanand
Satav, Shri Rajeev
Sathyabama, Shrimati V.
Satpathy, Shri Tathagata
Sawaikar, Adv. Narendra Keshav
Sawant, Shri Arvind
*Senthilnathan, Shri P. R.
Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi
 Shanavas, Shri M.I.
Sharma, Dr. Mahesh
Shekhawat, Shri Gajendra Singh
Shetty, Shri Gopal
Shewale, Shri Rahul
Shinde, Dr. Shrikant Eknath
Shirole, Shri Anil

Shyal, Dr. Bhartiben D.
Siddeshwara, Shri G. M.
Sigriwal, Shri Janardan Singh
Simha, Shri Pratap
Singh, Dr. Jitendra
Singh, Dr. Nepal
Singh, Dr. Prabhas Kumar
Singh, Dr. Satya Pal
Singh, Dr. Yashwant
Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar
Singh, Kunwar Bharatendra
Singh, Shri Abhishek
*Singh, Shri Bharat
Singh, Shri Bhola
Singh, Shri Dushyant
Singh, Shri Ganesh
Singh, Shri Hukum
Singh, Shri Lallu
Singh, Shri Nagendra
Singh, Shri Pashupati Nath
Singh, Shri R. K.
Singh, Shri Rajnath
Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer
Singh, Shri Rakesh
Singh, Shri Ravneet
Singh, Shri Satyapal
Singh, Shri Sunil Kumar
Singh, Shri Sushil Kumar
Singh, Shri Uday Pratap
Solanki, Dr. Kirit P.
Somaiya, Dr. Kirit
Sonkar, Shri Vinod Kumar
Sonker, Shrimati Neelam
Sonowal, Shri Sarbananda
Sriram, Shri Malyadri
Sriramulu, Shri B.
□ Sundaram, Shri P. R.
Suresh, Shri D.K.
Suresh, Shri Kodikunnil

*Swaraj, Shrimati Sushma
Tadas, Shri Ramdas C.
Tamta, Shri Ajay
Tanwar, Shri Kanwar Singh
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi
Teli, Shri Rameshwar
Teni, Shri Ajay Misra
Thambidurai, Dr. M.
Tharoor, Dr. Shashi
Thomas, Prof. K.V.
Tiwari, Shri Manoj
*Tomar, Shri Narendra Singh
Tripathi, Shri Sharad
Trivedi, Shri Dinesh
Udhayakumar, Shri M.
Usendi, Shri Vikram
Utawal, Shri Manohar
Vanaroja, Shrimati R.
Vardhan, Dr. Harsh
Vasanthi, Shrimati M.
Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai
Velagapalli, Shri Varaprasad Rao
*Venkatesh Babu, Shri T. G.
*Venugopal, Dr. P.
Verma, Dr. Anshul
Verma, Shri Bhanu Pratap Singh
Verma, Shri Rajesh
Verma, Shrimati Rekha
Vichare, Shri Rajan
Wanga, Shri Chintaman Navasha
Yadav, Shri Hukmdeo Narayan
*Yadav, Shri Om Prakash
*Yediyurappa, Shri B.S.

NOES

Nil

ABSTAIN

Nil

HON. SPEAKER: Subject to correction□, the result of the Division is:

Ayes: 318

Noes: 000

Abstain: 000

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

HON. SPEAKER: The lobbies may be opened for some time.

First Schedule, Second Schedule and Third Schedule

HON. SPEAKER: There are no amendments to the First, Second and Third Schedules. If the House agrees, I shall put all the Schedules together to the vote of the House in which case the result of the voting by Division shall be taken as applicable to each Schedule.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: Let the Lobbies be cleared --

Now, the Lobbies have been cleared.

So, as agreed, I shall now put the First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule to the vote of the House.

The question is:

"That the First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule stand part of the Bill."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO. 4 AYES 18:03 Hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa, Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Antony, Shri Anto

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra
Badal, Shrimati Harsimrat Kaur
Baheria, Shri Subhash Chandra
Bais, Shri Ramesh
Bala, Shrimati Anju
Balyan, Dr. Sanjeev
Bandyopadhyay, Shri Sudip
Banerjee, Shri Kalyan
*Banerjee, Shri Prasun
Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti
Basheer, Shri E. T. Mohammad
Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai
Bhagat, Shri Bodh Singh
Bhagat, Shri Sudarshan
Bhamre, Dr. Subhash Ramrao
Bharathi Mohan, Shri R.K.
Bharti, Sushri Uma
Bhatt, Shrimati Ranjanben
Bhuria, Shri Dileep Singh
Bidhuri, Shri Ramesh
Biju, Shri P. K.
Birla, Shri Om
Bohra, Shri Ramcharan
Bose, Prof. Sugata
Chand, Shri Nihal
Chandel, Kunwar Pushpendra Singh
Chaudhary, Shri C. R.
Chaudhary, Shri Haribhai
Chaudhary, Shri P.P.
Chaudhary, Shri Pankaj
Chaudhary, Shri Ram Tahal
Chaudhary, Shri Santokh Singh
Chaudhury, Shri Jitendra
Chauhan, Shri P. P.
Chautala, Shri Dushyant
Chavan, Shri Harishchandra
Chavda, Shri Vinod Lakhmashi
Chhewang, Shri Thupstan
Chhotelal, Shri
Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar
Choudhary, Shri Birendra Kumar
Chouhan, Shri Nandkumar Singh
Chowdhury, Shri Adhir Ranjan
Chudasama, Shri Rajeshbhai
Danve, Shri Raosaheb Patil
Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh
*Datta, Shri Sankar Prasad
Dattatreya, Shri Bandaru
Deka, Shri Ramen
*Dev, Kumari Sushmita
Devi, Shrimati Rama
Devi, Shrimati Veena
Dharambir, Shri
Dhotre, Shri Sanjay
Dhruvanarayana, Shri R.
Dhurve, Shrimati Jyoti
Dohre, Shri Ashok Kumar
Diwakar, Shri Rajesh Kumar
Dubey, Shri Nishikant
Dubey, Shri Satish Chandra
Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish
*Elumalai, Shri V.
Gaddigoudar, Shri P.C.
Gaikwad, Dr. Sunil Baliram
Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal
Gandhi, Shri Rahul
Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay
Gandhi, Shrimati Sonia
Gangwar, Shri Santosh Kumar
Gautam, Shri Satish Kumar
Geete, Shri Anant Gangaram
Ghosh, Shrimati Arpita
Giluwa, Shri Laxman
Gogoi, Shri Gaurav
*Gohain, Shri Rajen
*Gopal, Dr. K.
Gopalakrishnan, Shri C.
Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda
Gowda, Shri S.P. Muddahanume
Gupta, Shri Sudheer
Gurjar, Shri Krishanpal
Hansdak, Shri Vijay Kumar
*Hari, Shri G.
Haribabu, Dr. Kambhampati
Hooda, Shri Deepender Singh
Jadhav, Shri Sanjay Haribhau
Jaiswal, Dr. Sanjay
Jardosh, Shrimati Darshana Vikram
Jat, Prof. Sanwar Lal
Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh
Jayavardhan, Dr. J.
Jigajinagi, Shri Ramesh
Joshi, Dr. Murli Manohar
Joshi, Shri Chandra Prakash
Joshi, Shri Pralhad
Jyoti, Sadhvi Niranjana
 Kalvakuntla, Shrimati kavitha
Kamaraj, Dr. K.
Karandlaje, Kumari Shobha
Karunakaran, Shri P.
Kashyap, Shri Dinesh
Kashyap, Shri Virender
Kaswan, Shri Rahul
Kataria, Shri Rattan Lal
Kateel, Shri Nalin Kumar
Kaushik, Shri Ramesh Chander
*Khan, Shri Md. Badaruddoza
Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.
Khanna, Shri Vinod
Kharge, Shri Mallikarjun
Khuba, Shri Bhagwanth
Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu
Kishore, Shri Jugal
Kishore, Shri Kaushal
Koli, Shri Bahadur Singh
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh
Kumar, Dr. Virendra
Kumar, Kunwar Sarvesh
Kumar, Shri Dharmendra
Kumar, Shri K. Ashok
Kumar, Shri Kaushalendra
Kumar, Shri P.
Kumar, Shri Shanta
Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai
Kushawaha, Shri Ravinder
Lekhi, Shrimati Meenakashi
Lokhande, Shri Sadashiv
Maharaj, Dr. Swami Sakshiji
Mahato, Dr. Banshilal
Mahato, Dr. Mriganka
Mahato, Shri Bidyut Baran
Mahtab, Shri Bhartruhari
Mahendran, Shri C.
Majhi, Shri Balbhadra
Mandal, Dr. Tapas
Manjhi, Shri Hari
Marabi, Shri Kamal Bhan Singh
Maragatham, Shrimati K.
Maurya, Shri Keshav Prasad
Meena, Shri Arjun Lal
Meena, Shri Harish
Meghwal, Shri Arjun Ram
 Mishra, Shri Anoop
Mishra, Shri Bhairon Prasad
Mishra, Shri Daddan
Mishra, Shri Janardan
Mishra, Shri Kalraj
Modi, Shri Narendra
Mohan, Shri M. Murli
Mohan, Shri P.C.
Mohapatra, Dr. Sidhant
*Moily, Shri M. Veerappa
Mukherjee, Shri Abhijit
Munda, Shri Karia
Munde, Dr. Pritam Gopinath

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Naik, Shri Shripad Yesso

*Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

*Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paraste, Shri Dalpat Singh

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

□ Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai
Poddar, Shrimati Aparupa
Prabakaran, Shri K. R. P.
Pradhan, Shri Nagendra Kumar
Prasad, Dr. Bhagirath
Pratap, Shri Krishan
 Premachandran, Shri N.K.
Raajhaa, Shri A. Anwhar
Radhakrishnan, Shri Pon
Radhakrishnan, Shri R.
*Raghavan, Shri M.K.
Rai, Shri Nityanand
Raj, Shrimati Krishna
Rajbhar, Shri Harinarayan
Rajendran, Shri S.
Rajesh, Shri M. B.
Rajoria, Dr. Manoj
Rajput, Shri Mukesh
Raju, Shri Ashok Gajapathi
Raju, Shri Gokaraju Ganga
Ram, Shri Janak
Ram, Shri Vishnu Dayal
Ramachandran, Shri K. N.
Ramachandran, Shri Mullappally
Rao, Shri M. Venkateswara
Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa
Rathod, Shri D.S.
Rathore, Col. Rajyavardhan
Rathwa, Shri Ramsinh
Raut, Shri Vinayak Bhaurao
Raval, Shri Paresh
Rawat, Shrimati Priyanka Singh
Ray, Shri Bishnu Pada
Ray, Shri Ravindra Kumar
Reddy, Shri J.C. Divakar
Reddy, Shri Konda Vishweshwar
Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan
 Reddy, Shri P. Srinivasa
Reddy, Shri Y. V. Subba
*Renuka, Shrimati Butta

Rijju, Shri Kiren
Rio, Shri Neiphiu
Roy, Prof. Saugata
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Sahu, Shri Chandulal
Sahu, Shri Lakhan Lal
Sai, Shri Vishnu Dev
Saini, Shri Rajkumar
Salim, Shri Mohammad
Samal, Dr. Kulmani
Sampla, Shri Vijay
Sampath, Dr. A.
*Sanghamita, Dr. Mamta
Sanjar, Shri Alok
Saren, Dr. Uma
Sarmah, Shri Ram Prasad
Sarswati, Shri Sumedhanand
Satav, Shri Rajeev
Sathyabama, Shrimati V.
Satpathy, Shri Tathagata
Sawaikar, Adv. Narendra Keshav
Sawant, Shri Arvind
□ Senthilnathan, Shri P. R.
Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi
*Shanavas, Shri M.I.
Sharma, Dr. Mahesh
Shekhawat, Shri Gajendra Singh
Shetty, Shri Gopal
Shewale, Shri Rahul
Shinde, Dr. Shrikant Eknath
Shirole, Shri Anil
Shyal, Dr. Bhartiben D.
Siddeshwara, Shri G. M.
Sigriwal, Shri Janardan Singh
Simha, Shri Pratap
Singh, Dr. Jitendra
Singh, Dr. Nepal
Singh, Dr. Prabhas Kumar
Singh, Dr. Satya Pal
Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar
Singh, Kunwar Bharatendra
Singh, Rao Inderjit
Singh, Shri Abhishek
Singh, Shri Bharat
Singh, Shri Bhola
Singh, Shri Dushyant
Singh, Shri Ganesh
Singh, Shri Hukum
Singh, Shri Kirti Vardhan
Singh, Shri Lallu
Singh, Shri Nagendra
Singh, Shri Pashupati Nath
Singh, Shri R. K.
Singh, Shri Rajnath
Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer
Singh, Shri Rakesh
Singh, Shri Rama Kishore
Singh, Shri Ravneet
Singh, Shri Satyapal
Singh, Shri Sunil Kumar
Singh, Shri Sushil Kumar
Singh, Shri Uday Pratap
Singh, Shri Virendra
Solanki, Dr. Kirit P.
Somaiya, Dr. Kirit
Sonkar, Shri Vinod Kumar
Sonker, Shrimati Neelam
Sonowal, Shri Sarbananda
Sriram, Shri Malyadri
Sriramulu, Shri B.
 Sundaram, Shri P. R.
Suresh, Shri D.K.
Suresh, Shri Kodikunnil
Swaraj, Shrimati Sushma
Tadas, Shri Ramdas C.
Tamta, Shri Ajay
Tanwar, Shri Kanwar Singh
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar
Teni, Shri Ajay Misra
Thambidurai, Dr. M.
*Tharoor, Dr. Shashi
Thomas, Prof. K.V.
Tiwari, Shri Manoj
Tomar, Shri Narendra Singh
Tripathi, Shri Sharad
Trivedi, Shri Dinesh
Udhayakumar, Shri M.
Usendi, Shri Vikram
Utawal, Shri Manohar
Vanaroja, Shrimati R.
Vardhan, Dr. Harsh
Vasanthi, Shrimati M.
Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai
Velagapalli, Shri Varaprasad Rao
*Venkatesh Babu, Shri T. G.
Venugopal, Dr. P.
Venugopal, Shri K. C.
Verma, Dr. Anshul
Verma, Shri Bhanu Pratap Singh
Verma, Shri Rajesh
Verma, Shrimati Rekha
Vichare, Shri Rajan
Wanga, Shri Chintaman Navasha
Yadav, Shri Hukmdeo Narayan
Yadav, Shri Om Prakash
Yediyurappa, Shri B.S.

NOES

Nil

ABSTAIN

Nil

HON. SPEAKER: Subject to correction[□], the result of the Division is:

Ayes: 333

Noes: 000

Abstain: 000

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

*The First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule
were added to the Bill.*

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: Now the Minister may move that the Bill, as amended, be passed.

श्रीमती सुआमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, पूंन यह है :

"कि कियेक को संशोधित रूप में पारित किया जाए,"

HON. SPEAKER: Before I put the Bill, as amended, be passed, to vote of the House, I would like to say that this being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division.

Now, the lobbies are already clear.

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided:

DIVISION NO.5 AYES 18:06 Hrs.

Adityanath, Yogi

Adsul, Shri Anandrao

Advani, Shri L.K.

Agrawal, Shri Rajendra

Ahir, Shri Hansraj Gangaram

Ahlawat, Shrimati Santosh

*Ahluwalia, Shri S.S.

Ali, Shri Idris

Amarappa , Shri Karadi Sanganna

Ananthkumar, Shri

Angadi, Shri Suresh C.

Antony, Shri Anto

Arunmozhithevan, Shri A.

Azad, Shri Kirti

Babu, Dr. Ravindra

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur
Baheria, Shri Subhash Chandra
Bais, Shri Ramesh
Bala, Shrimati Anju
Balyan, Dr. Sanjeev
Bandyopadhyay, Shri Sudip
Banerjee, Shri Kalyan
 Banerjee, Shri Prasun
Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti
Basheer, Shri E. T. Mohammad
Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai
Bhagat, Shri Bodh Singh
Bhagat, Shri Sudarshan
Bhamre, Dr. Subhash Ramrao
 Bharathi Mohan, Shri R.K.
Bharti, Sushri Uma
Bhatt, Shrimati Ranjanben
Bhuria, Shri Dileep Singh
Bidhuri, Shri Ramesh
Biju, Shri P. K.
Birla, Shri Om
*Biswas, Shri Radheshyam
Bohra, Shri Ramcharan
Bose, Prof. Sugata
Chand, Shri Nihal
Chandel, Kunwar Pushpendra Singh
Chaudhary, Shri C. R.
Chaudhary, Shri Haribhai
Chaudhary, Shri P.P.
Chaudhary, Shri Pankaj
Chaudhary, Shri Ram Tahal
Chaudhary, Shri Santokh Singh
Chaudhury, Shri Jitendra
Chauhan, Shri P. P.
*Chautala, Shri Dushyant
Chavan, Shri Harishchandra
Chavda, Shri Vinod Lakhmashi
Chhewang, Shri Thupstan
Chhotelal, Shri
Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara

Choubey, Shri Ashwini Kumar
Choudhary, Shri Birendra Kumar
Chouhan, Shri Nandkumar Singh
Chowdhury, Shri Adhir Ranjan
Chudasama, Shri Rajeshbhai
Danve, Shri Raosaheb Patil
Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh
*Datta, Shri Sankar Prasad
Dattatreya, Shri Bandaru
Deka, Shri Ramen
*Dev, Kumari Sushmita
Devi, Shrimati Rama
Devi, Shrimati Veena
Dharambir, Shri
Dhotre, Shri Sanjay
Dhruvanarayana, Shri R.
Dhurve, Shrimati Jyoti
Dohre, Shri Ashok Kumar
Diwakar, Shri Rajesh Kumar
Dubey, Shri Nishikant
Dubey, Shri Satish Chandra
Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish
*Elumalai, Shri V.
Gaddigoudar, Shri P.C.
Gaikwad, Dr. Sunil Baliram
Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal
Gandhi, Shri Rahul
Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay
Gandhi, Shrimati Sonia
Gangwar, Shri Santosh Kumar
Gautam, Shri Satish Kumar
Geete, Shri Anant Gangaram
Ghosh, Shrimati Arpita
Giluwa, Shri Laxman
Gogoi, Shri Gaurav
Gohain, Shri Rajen
*Gopal, Dr. K.
Gopalakrishnan, Shri C.
Gopalakrishnan, Shri R.

Gowda, Shri D.V. Sadananda
Gowda, Shri S.P. Muddahanume
Gupta, Shri Sudheer
Gurjar, Shri Krishanpal
Hansdak, Shri Vijay Kumar
*Hari, Shri G.
Haribabu, Dr. Kambhampati
*Hooda, Shri Deepender Singh
Jadhav, Shri Sanjay Haribhau
Jaiswal, Dr. Sanjay
Jardosh, Shrimati Darshana Vikram
Jat, Prof. Sanwar Lal
Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh
Jayavardhan, Dr. J.
Jigajinagi, Shri Ramesh
Joshi, Dr. Murli Manohar
Joshi, Shri Chandra Prakash
Joshi, Shri Pralhad
Jyoti, Sadhvi Niranjana
 Kalvakuntla, Shrimati kavitha
Kamaraj, Dr. K.
Karandlaje, Kumari Shobha
Karunakaran, Shri P.
Kashyap, Shri Dinesh
Kashyap, Shri Virender
Kaswan, Shri Rahul
Kataria, Shri Rattan Lal
Kateel, Shri Nalin Kumar
Kaushik, Shri Ramesh Chander
*Khan, Shri Md. Badaruddoza
Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.
Khanna, Shri Vinod
Kharge, Shri Mallikarjun
Khuba, Shri Bhagwanth
Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu
Kishore, Shri Jugal
Kishore, Shri Kaushal
Koli, Shri Bahadur Singh
Koshyari, Shri Bhagat Singh
Kristappa, Shri N.

Kulaste, Shri Faggan Singh
Kumar, Dr. Virendra
Kumar, Kunwar Sarvesh
Kumar, Shri Dharmendra
Kumar, Shri K. Ashok
Kumar, Shri Kaushalendra
Kumar, Shri P.
Kumar, Shri Shanta
Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai
Kushawaha, Shri Ravinder
Lekhi, Shrimati Meenakashi
Lokhande, Shri Sadashiv
Maharaj, Dr. Swami Sakshiji
Mahato, Dr. Banshilal
Mahato, Dr. Mriganka
Mahato, Shri Bidyut Baran
Mahtab, Shri Bhartruhari
Mahendran, Shri C.
Majhi, Shri Balbhadra
Mandal, Dr. Tapas
Manjhi, Shri Hari
Marabi, Shri Kamal Bhan Singh
Maragatham, Shrimati K.
Maurya, Shri Keshav Prasad
Meena, Shri Arjun Lal
Meena, Shri Harish
Meghwal, Shri Arjun Ram
Mishra, Shri Anoop
Mishra, Shri Bhairon Prasad
Mishra, Shri Daddan
Mishra, Shri Janardan
Mishra, Shri Kalraj
Modi, Shri Narendra
Mohan, Shri M. Murli
Mohan, Shri P.C.
Mohapatra, Dr. Sidhant
□ Moily, Shri M. Veerappa
Mukherjee, Shri Abhijit
Munda, Shri Karia
Munde, Dr. Pritam Gopinath

Muniyappa, Shri K.H.

Nagar, Shri Rodmal

Nagarajan, Shri P.

Naik, Shri Shripad Yesso

*Narasimham, Shri Thota

Nath, Shri Chand

Natterjee, Shri J.J.T.

Nete, Shri Ashok Mahadeorao

Nishad, Shri Ajay

Nishad, Shri Ram Charitra

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal

Oram, Shri Jual

Paatle, Shrimati Kamla

*Pala, Shri Vincent H.

Pandey, Dr. Mahendra Nath

Pandey, Shri Hari Om

Pandey, Shri Rajesh

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Paraste, Shri Dalpat Singh

Parasuraman, Shri K.

Parthipan, Shri R.

Paswan, Shri Chhedi

Paswan, Shri Chirag

Paswan, Shri Kamlesh

Paswan, Shri Ram Chandra

Paswan, Shri Ramvilas

Patasani, Shri Prasanna Kumar

Patel, Dr. K. C.

Patel, Shri Devji M.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai

Patel, Shri Prahlad Singh

Patel, Shri Subhash

Patel, Shrimati Jayshreeben

Pathak, Shrimati Riti

Patil, Shri C. R.

Patil, Shri Kapil Moreshwar

Patil, Shri Sanjay Kaka

Patole, Shri Nana

Phule, Sadhvi Savitri Bai

Poddar, Shrimati Aparupa
Prabakaran, Shri K. R. P.
Pradhan, Shri Nagendra Kumar
Prasad, Dr. Bhagirath
Pratap, Shri Krishan
Premachandran, Shri N.K.
Raajhaa, Shri A. Anwhar
Radhakrishnan, Shri Pon
Radhakrishnan, Shri R.
*Raghavan, Shri M.K.
Rai, Shri Nityanand
Raj, Shrimati Krishna
Rajbhar, Shri Harinarayan
Rajendran, Shri S.
Rajesh, Shri M. B.
Rajoria, Dr. Manoj
Rajput, Shri Mukesh
Raju, Shri Ashok Gajapathi
Raju, Shri Gokaraju Ganga
Ram, Shri Janak
Ram, Shri Vishnu Dayal
Ramachandran, Shri K. N.
Ramachandran, Shri Mullappally
Rao, Shri M. Venkateswara
Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa
Rathod, Shri D.S.
Rathore, Col. Rajyavardhan
Rathwa, Shri Ramsinh
Raut, Shri Vinayak Bhaurao
Raval, Shri Paresh
Rawat, Shrimati Priyanka Singh
Ray, Shri Bishnu Pada
Ray, Shri Ravindra Kumar
Reddy, Shri J.C. Divakar
Reddy, Shri Konda Vishweshwar
Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan
*Reddy, Shri P. Srinivasa
Reddy, Shri Y. V. Subba
*Renuka, Shrimati Butta

Rijju, Shri Kiren
Rio, Shri Neiphiu
Roy, Prof. Saugata
Rudy, Shri Rajiv Pratap
Sahu, Shri Chandulal
Sahu, Shri Lakhan Lal
Sai, Shri Vishnu Dev
Saini, Shri Rajkumar
Salim, Shri Mohammad
Samal, Dr. Kulmani
Sampla, Shri Vijay
Sampath, Dr. A.
*Sanghamita, Dr. Mamta
Sanjar, Shri Alok
Saren, Dr. Uma
Sarmah, Shri Ram Prasad
Sarswati, Shri Sumedhanand
Satav, Shri Rajeev
Sathyabama, Shrimati V.
Satpathy, Shri Tathagata
Sawaikar, Adv. Narendra Keshav
Sawant, Shri Arvind
□ Senthilnathan, Shri P. R.
Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi
*Shanavas, Shri M.I.
Sharma, Dr. Mahesh
Shekhawat, Shri Gajendra Singh
Shetty, Shri Gopal
Shewale, Shri Rahul
Shinde, Dr. Shrikant Eknath
Shirole, Shri Anil
Shyal, Dr. Bhartiben D.
Siddeshwara, Shri G. M.
Sigriwal, Shri Janardan Singh
Simha, Shri Pratap
Singh, Dr. Jitendra
Singh, Dr. Nepal
Singh, Dr. Prabhas Kumar
Singh, Dr. Satya Pal
Singh, Dr. Yashwant

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar
Singh, Kunwar Bharatendra
Singh, Rao Inderjit
Singh, Shri Abhishek
Singh, Shri Bharat
Singh, Shri Bhola
Singh, Shri Dushyant
Singh, Shri Ganesh
Singh, Shri Hukum
Singh, Shri Kirti Vardhan
Singh, Shri Lallu
Singh, Shri Nagendra
Singh, Shri Pashupati Nath
Singh, Shri R. K.
Singh, Shri Rajnath
Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer
Singh, Shri Rakesh
Singh, Shri Rama Kishore
Singh, Shri Ravneet
Singh, Shri Satyapal
Singh, Shri Sunil Kumar
Singh, Shri Sushil Kumar
Singh, Shri Uday Pratap
Singh, Shri Virendra
Solanki, Dr. Kirit P.
Somaiya, Dr. Kirit
Sonkar, Shri Vinod Kumar
Sonker, Shrimati Neelam
Sonowal, Shri Sarbananda
Sriram, Shri Malyadri
Sriramulu, Shri B.
 Sundaram, Shri P. R.
Suresh, Shri D.K.
Suresh, Shri Kodikunnil
Swaraj, Shrimati Sushma
Tadas, Shri Ramdas C.
Tamta, Shri Ajay
Tanwar, Shri Kanwar Singh
Tasa, Shri Kamakhya Prasad
Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi

Teli, Shri Rameshwar
Teni, Shri Ajay Misra
Thambidurai, Dr. M.
*Tharoor, Dr. Shashi
Thomas, Prof. K.V.
Tiwari, Shri Manoj
*Tomar, Shri Narendra Singh
Tripathi, Shri Sharad
Trivedi, Shri Dinesh
Udhayakumar, Shri M.
Usendi, Shri Vikram
Utawal, Shri Manohar
Vanaroja, Shrimati R.
Vardhan, Dr. Harsh
Vasanthi, Shrimati M.
Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai
Velagapalli, Shri Varaprasad Rao
Venkatesh Babu, Shri T. G.
Venugopal, Dr. P.
Venugopal, Shri K. C.
Verma, Dr. Anshul
Verma, Shri Bhanu Pratap Singh
Verma, Shri Rajesh
Verma, Shrimati Rekha
Vichare, Shri Rajan
Wanga, Shri Chintaman Navasha
Yadav, Shri Hukmdeo Narayan
Yadav, Shri Om Prakash
Yediyurappa, Shri B.S.

NOES

Nil

ABSTAIN

Nil

HON. SPEAKER: Subject to correction[□], the result of the Division is:

Ayes: 331

Noes: 000

Abstain: 000

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Bill, as amended, is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Lobbies may be opened now.

The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 8th May, 2015, at 11 a.m..

18.14 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, May 8, 2015/Vaishakha 18, 1937 (Saka).